छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 185 ■ अम्बिकापुर, शुक्रवार 17 जुलाई 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

देश का पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट विधानसभा में पास, व्यापारियों को बड़ी राहत

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरूवार को 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026' पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम एवं विश्वास आधारित बिजनेस परमीशन सिस्टम लागू होगा।

इस अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों एवं कारोबार की स्थापना और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना तथा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अधिक पारदर्शी, तेज और उद्यम-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है। अधिनियम के तहत उद्योगों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न जोखिम श्रेणियों में किया जाएगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को सरल एवं त्वरित मंजूरी मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध स्वीकृति की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। इससे छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

मिलेगी यह सुविधा-नई व्यवस्था के अंतर्गत कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों के स्थान पर सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा लाइसेंसधारी अभियंता, आर्किटेक्ट या अन्य अधिकृत पेशेवरों द्वारा प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अनुमतियों की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक जवाबदेह बनेगी। अधिनियम के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार के विस्तार एवं संचालन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

पात्र मामलों में अनुमति स्वत:-एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय संबंधी अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर, सोसायटी अथवा फर्म का पंजीयन समयबद्ध प्रक्रिया से तथा भवन अनुज्ञा सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जा सकेगी। निर्धारित समय-सीमा में संबंधित विभाग द्वारा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में पात्र मामलों में अनुमति स्वत: स्वीकृत माना जाएगा। हालांकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी परीक्षण एवं भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

आठ विभाग की 43 सेवाएं शामिल

अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन के 8 विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली 43 सेवाओं को जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली के दायरे में शामिल किया गया है। आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका परिषद की मंजूरी से अतिरिक्त सेवाएं भी इसमें जोड़ी जा सकेंगी। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति इसके क्रियान्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी निभाएगी। दोनों समितियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी।

उद्यमों को प्रत्यक्ष लाभ-इस सुधार से राज्य के 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि भरोसे, स्व-घोषणा और समयबद्ध सेवाओं पर आधारित यह व्यवस्था कारोबार शुरू करने और संचालित करने में लगने वाले समय एवं लागत को कम करेगी, जबकि अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' राज्य में पारदर्शी, सरल, पूर्वानुमेय और निवेश-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

धनबाद के वारंटी गैंगस्टर को पुलिस से छुड़ाकर भगाने वाले 2 गिरफ्तार

अन्य फरार आरोपियों के तलाश में लगी पुलिस

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। वासेपुर हत्याकांड से जुड़े, धनबाद बैंकमोड़ थाना के एक गैंगस्टर वारंटी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाकर भगाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिश्ते में पिता-पुत्र हैं। घटना बीते 29 जून की है।

थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा ने बताया कि, धनबाद बैंकमोड़ थाना के उपनिरीक्षक अभय कुमार अपनी टीम के साथ 29 जून को सुबह करीब 8 बजे अंबिकापुर आए थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि धनबाद के वारंटी साबिर आलम पिता सालार आलम निवासी कमर मखदूमी रोड वासेपुर अपनी पहचान छिपाकर मोमिनपुरा में रह रहा है।

धनबाद पुलिस ने मोमिनपुरा मस्जिद के पास स्कूटी से आते एक व्यक्ति को रोका। पूछताछ में उसने अपना नाम साबिर आलम बताया। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही थी, तभी साबिर शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाने लगा। इसी दौरान जुनैद खान और मोहम्मद जाहिद खान सहित अन्य लोग वहां पहुंचे और सामूहिक बल प्रयोग करके वारंटी को पुलिस की वैध अभिरक्षा से छुड़ा लिया। मौके का फायदा उठाकर साबिर आलम भीड़ के साथ भाग निकला।

इस संबंध में धनबाद पुलिस की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 438/26 धारा 221, 132, 126(2), 296(बी), 351(3), 263(ई), 352, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

वीडियो कॉल से हुई पहचान

विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थी और गवाहों के बयान लिए। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। धनबाद पुलिस के उपनिरीक्षक अभय कुमार से वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ करके आरोपियों की पहचान कराई गई। वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के जरिए जुनैद खान पिता मोहम्मद जाहिद खान 30 वर्ष और मोहम्मद जाहिद खान पिता मोहम्मद अयुब खान 59 वर्ष दोनों निवासी नया बस्ती हबीबनगर अंबिकापुर की पहचान पुख्ता हुई। दोनों से पूछताछ में घटना करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

अन्य आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार मामले में शामिल अन्य आरोपी घटना के दिन से फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। वारंटी साबिर आलम की गिरफ्तारी के लिए भी धनबाद पुलिस के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जा रही है। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी शशिकान्त सिन्हा, एएसआई अदीप प्रताप सिंह व विवेक पाण्डेय एवं साइबर टीम सक्रिय रही।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

धारा 221-लोक सेवक को कर्तव्य से भ्रष्ट करने के लिए हमला, धारा 132-लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला, धारा 126(2)-गलत तरीके से रोकना, धारा 351(3)-आपराधिक धमकी, धारा 3(5)-सामान्य आशय।

कोतवाली के सामने महिला अधिकारी के गले से सोने का चैन खींचकर भागे बाइक सवार

हेलमेट लगाये आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम, 2 आरोपी सीसीटीवी में कैद

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर कोतवाली थाना व नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने दिन-दहाड़े जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एक महिला अधिकारी चैन स्नैचिंग का शिकार हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों के तलाश में लगी है। हेलमेट पहने आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया।

जानकारी के मुताबिक, पूनम तिवारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हैं। वे गुरूवार को रोजाना की भांति अपने कार्यालय से दोपहर के समय खाना खाने के लिये घर गई थीं। घर से वापस आने के बाद अपनी स्कूटी वाहन को

कार्यालय के गेट के सामने खड़ा करके अंदर जाने को हुईं, इसी बीच हेलमेट पहने 2 बाइक सवार युवकों ने उनके गले से तीन तोला वजनी सोने का चेन झपट लिया और थाना चौक से होते महामाया चौक की ओर निकल गये। सोने के चेन की कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई जा रही है।

महिला अधिकारी के शोर मचाने पर कार्यालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारी बाहर निकले, इन्हें अधिकारी ने घटना की जानकारी दी। कोतवाली थाना और नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हुई चैन स्नेचिंग की इस घटना से हड़कम्प की स्थिति बन गई। इसकी सूचना तत्काल कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, और महिला अधिकारी से घटना की जानकारी ली।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चेन स्नैचिंग की इस वारदात के बाद एक बार फिर स्नेचरों की सक्रियता सामने आई है। इसके पहले अप्रैल माह में शहर के सीतापुर क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट झपट लिया था, वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। अंबिकापुर में लम्बे समय बाद इस प्रकार की घटना सामने आई है।

स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से 4.22 लाख रुपये की चोरी

छ.ग.फ्रंटलाइन सीतापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भवराडांड में स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के शटर का ताला तोड़कर काउंटर में रखे 4 लाख 22 हजार रुपये को अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, थाना क्षेत्र के ग्राम नंदीटिकरा, भवराडांड का सत्यनारायण कुशवाहा गांव में ही स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र का संचालन करता है। आठ जुलाई को वह स्टेट बैंक सीतापुर से चेक के माध्यम से 03 लाख 20 हजार रुपये एवं प्रवीण गुप्ता के पास से यूपीआई के माध्यम से 01 लाख 2000 रुपये, कुल 4 लाख 22 हजार रुपये ग्राहक को बांटने के लिए लेकर आया, और ग्राहक सेवा केन्द्र में ही झोला में रुपये डालकर काउंटर में रखा था। 10 जुलाई को लगभग 6.30 बजे वह अपने ग्राहक सेवा केन्द्र को बंद करके अपने रूम में चले गया था। 11 जुलाई को सुबह लगभग 04 बजे अज्ञात चोरों ने बाहर के शटर को तोड़कर ग्राहक सेवा केन्द्र में रखे लगभग 4 लाख 22 हजार रुपये चोरी कर लिया। काफी तलाश के बाद भी चोर का पता नहीं चलने पर उसने घटना की जानकारी सीतापुर थाने में दी है, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 331(4), 305(ए) का मामला दर्ज कर लिया है।

ट्रक के पहिये के नीचे दबी महिला का हाथ कटकर अलग हुआ

शहर के गांधी चौक की घटना, बाइक का चक्का गड्ढे में जाने से बनी गंभीर स्थिति

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के गांधी चौक में ट्रक के पहिये के नीचे आई महिला का हाथ कुचलकर पूरी तरह से अलग हो गया। महिला के सीने का एक हिस्सा भी ट्रक के पहिए के नीचे दब गया। ट्रक चालक के सूझ-बूझ से उसकी जान बच गई। ट्रक को बैक करके महिला को बाहर निकाला गया। महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, वहां सड़क किनारे एक गड्ढा है। बारिश के दिनों में यह गड्ढा और खतरनाक हो जाता है। यहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक अनियंत्रित हो जाते हैं। ऐसे में यह गड्ढा कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे बाइक में सवार होकर एक महिला अपने रिश्तेदार के साथ गांधी चौक के पास पहुंची थी। इस दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी 1097 का चालक महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धीरे-धीरे वाहन को मोड़कर रिंग रोड पर आकाशवाणी चौक की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार महिला-पुरुष ने ट्रक के बाएं साइड से आगे

निकलने का प्रयास किया, और बाइक का चक्का गड्ढे में चले गया, जिससे अनियंत्रित हुई महिला सड़क पर गिरकर ट्रक के अगले पहिए के नीचे आ गई और उसका हाथ बुरी तरह से कुचल गया। महिला पेट के बल लेटी थी,सके सीने का कुछ हिस्सा भी जख्मी हुआ है। हादसे के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान ने ट्रक को धीरे-धीरे पीछे कराया, और घायल महिला को तत्काल पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिस्तर में अज्ञात जीव के काटने से युवक की हो गई मौत

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बलरामपुर जिला के थाना सनावल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुर्लूडीह में सोते समय अज्ञात जीव के काटने से एक युवक की इलाज के दौरान अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल में मौत हो गई।मृतक घटना के समय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कमरे में जमीन पर सो रहा था।

मृतक की पत्नी रजमतिया ने बताया कि, 14 जुलाई की रात करीब 12 बजे वह अपने पति अजय कुमार 36 वर्ष एवं 5 बच्चों के साथ एक ही कमरे में जमीन पर सो रही थी। रात में अचानक अजय कुमार हाथ-पैर पटकते हुए छटपटाने लगे। पूछने पर कहा कि कुछ काट दिया है। बिस्तर झाड़कर देखने पर कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद अजय बेहोश हो गया, जिससे कोहराम की स्थिति बन गई। शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग जमा हुए और सभी ने घायल को उपचार के लिए अंबिकापुर रवाना किया। उपचार के दौरान 16 जुलाई को चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है।

प्रारंभिक जांच में मौत का कारण अज्ञात जीव के काटने से होना माना जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मृत्यु सर्पदंश से हुई है, या किसी अन्य जीव के काटने से।

टूर ऑपरेटर्स ने अंबिकापुर के आतिथ्य और होटल सुविधाओं का लिया अनुभव

सरगुजा पर्यटन को नई उड़ान देने की पहल, पर्यटन संभावनाओं पर हुई सार्थक चर्चा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा सरगुजा संभाग के पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में आयोजित फेम ट्रिप से एक दिन पूर्व अंबिकापुर में विशेष होटल भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आमंत्रित टूर ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल एजेंट्स को सरगुजा में उपलब्ध उत्कृष्ट आवासीय सुविधाओं, आतिथ्य परंपरा तथा पर्यटन के अनुकूल अधोसंरचना से परिचित कराना था, ताकि वे भविष्य में अधिक से अधिक पर्यटकों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सकें। कार्यक्रम अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित टूर ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल एजेंट्स का होटल पर्पल आर्किड, अंबिकापुर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ तिलक लगाकर एवं स्वागत पेय के माध्यम से आत्मीय स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात अतिथियों को होटल की आधुनिक आवासीय व्यवस्था, स्वादिष्ट भोजन की सुविधाएं, बैंक्वेट हॉल तथा अन्य अतिथि सेवाओं का विस्तृत निरीक्षण कराया गया। होटल प्रबंधन ने अपने आतिथ्य और सेवाओं के माध्यम से सरगुजा की मेहमान नवाजी की समृद्ध परंपरा से सभी को परिचित कराया। दोपहर के

भोजन के उपरांत सभी अतिथियों को होटल माखन विहार ले जाया गया, यहां होटल प्रबंधन ने उन्हें उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, आवासीय व्यवस्थाओं तथा अन्य सेवाओं का अवलोकन कराया। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने होटल की गुणवत्ता, स्वच्छता और पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की।

होटल भ्रमण के बाद होटल संचालक द्वारा नि:शुल्क उच्च स्तरीय हाई-टी का आयोजन किया गया। इस दौरान सरगुजा संभाग के प्रमुख पर्यटन स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों, जनजातीय संस्कृति तथा पर्यटन विकास की संभावनाओं पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। टूर ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल एजेंट्स ने क्षेत्र में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं पर अपने सुझाव भी साझा किए। अंत में सभी टूर ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल एजेंट्स ने अंबिकापुर के होटलों में उपलब्ध उत्कृष्ट सुविधाओं और आत्मीय आतिथ्य की सराहना की और कहा कि सरगुजा संभाग प्रकृति, संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है तथा यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के परिचयात्मक भ्रमण से सरगुजा राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा तथा वे भविष्य में अधिक से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों को इस क्षेत्र की यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की यह पहल सरगुजा संभाग को एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे कार्यक्रम पर्यटन उद्योग, स्थानीय होटल व्यवसाय, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ब्याज के दबाव और धमकी से तंग आकर युवक किया था खुदकुशी, आरोपी गिरफ्तार

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। अत्यधिक ब्याज दर पर कर्ज देकर जान से मारने की धमकी देने से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में आरोपित पंकज चौधरी 50 वर्ष, निवासी राजेन्द्र वार्ड दर्रीपारा को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। मामले में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए थे।

थाना कोतवाली पुलिस ने बताया कि, मृतक संदीप अग्रवाल ने सुसाइड नोट में लिखा था कि आरोपित पंकज चौधरी उससे ब्याज और मूल रकम मांगकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने मर्ग जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक ट्रांजेक्शन और गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि पंकज चौधरी ने मृतक को कर्ज देकर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी कारण वह आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मृतक ने जीवित रहते हुए अपने पिता एवं पत्नी को भी इसकी जानकारी दी थी। सम्पूर्ण जांच पर पाया गया कि पंकज चौधरी के द्वारा मृतक संदीप अग्रवाल को अत्यधिक ब्याज दर पर रकम देकर, ब्याज व मूल वापस नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारण वह आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने धारा 108, 351(3) बीएनएस एवं 4 कर्जा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना कोतवाली से उप निरीक्षक केके यादव, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक मंटुलाल गुप्ता, शिव राजवाड़े सक्रिय रहे।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

कार्यालय तक सीमित न रहकर फील्ड विजिट करे अधिकारी, कर्मचारी : कलेक्टर

★ कलेक्टर ने की एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

★ एग्रीस्टेक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय कुसमी के सभाकक्ष कुसमी में एग्रीस्टेक योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित

विकासखंड कुसमी के समस्त पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,लोक सेवा केंद्र संचालक तथा संबंधित विभागों से एग्रीस्टेक पंजीयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए एग्रीस्टेक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अनमोल विवेक टोप्पो, तहसीलदार सुश्री रॉकी एक्का, जनपद सीईओ संजय दुबे उपस्थित रहे । उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक पंजीयन से किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं और धान खरीदी व्यवस्था से प्रभावी रूप से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए प्रत्येक पात्र किसान का पंजीयन समय-सीमा के भीतर पूर्ण करे।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले खरीफ विपणन वर्ष में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अभी से सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें।

कलेक्टर ने सभी पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से अपने हल्कों का भ्रमण करें। गांव-गांव पहुंचकर किसानों से सीधे संपर्क स्थापित करें, उनकी समस्याओं को समझें और मौके पर ही एग्रीस्टेक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने लोक सेवा केंद्र संचालकों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि लक्ष्य समय से पहले पूरा किया जा सके।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पटवारियों से एग्रीस्टेक पंजीयन की प्रगति की जानकारी ली। कई क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। केवल आंकड़ों के भरोसे नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम दिखाई देना आवश्यक है।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पटवारी अपने क्षेत्र में ऐसे किसानों की सूची तैयार करें जिनका अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है और उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित करें। यदि किसी किसान को दस्तावेजों या अन्य किसी कारण से परेशानी आ रही है तो उसका तत्काल समाधान करें ताकि कोई भी किसान शासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित न हो। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी, सभी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य समय-सीमा में पूर्ण करे।

भारी बारिश में भी नहीं टूटा आस्था का रथ, जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा बिश्रामपुर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोयलांचल बिश्रामपुर में भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम व बहन सुभद्रा की भव्य रथयात्रा ने आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का अद्भुत संदेश दिया। मूसलाधार बारिश भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर सकी। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयघोष, शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और भजन कीर्तन के बीच महाप्रभु का विशाल रथ मंदिर प्रांगण से निकला और पूरे नगर का भ्रमण करते हुए आरटीआई कॉलोनी स्थित ज्ञानदायिनी मां सरस्वती मंदिर महाप्रभु के मौसी के घर पहुंचा। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह-जगह महाप्रभु जगन्नाथ का स्वागत किया। धार्मिक महोत्सव की शुरुआत 29 जून को देव स्नान पूर्णिमा के साथ हुई थी। इसके बाद 14 जुलाई को नेत्र उत्सव, कड़ी-चावल भोग तथा भगवान के नवयौवन वेश के दर्शन कराए गए। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 16 जुलाई को आयोजित हुई भव्य श्री गुणिंचा रथयात्रा रही, जिसमें क्षेत्रभर से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक रहा। आयोजकों ने बताया कि 19 जुलाई को वार्षिक उत्सव, 20 जुलाई को हेरा पंचमी एवं महालक्ष्मी यात्रा, 24 जुलाई को बाहुड़ा यात्रा रथ वापसी, 25 जुलाई को भगवान का भव्य स्वर्ण वेश, 26 जुलाई को अधर पणा तथा 27 जुलाई को नीलाद्री प्रवेश के साथ महोत्सव का विधिवत समापन होगा। गुरुवार को रथयात्रा में राजा सेवादार के रूप में सरगुजा महाराज एवं प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विशेष रूप से शामिल हुए। उनके साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, विंध्येश्वर शरण सिंह, श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन शफी अहमद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह, सुभाष गोयल, नपं बिश्रामपुर के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव, शिवनंदनपुर नपं अध्यक्ष रितेश जायसवाल, बिश्रामपुर नपं

उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, शिवनंदनपुर उपाध्यक्ष अंशुल गोयल, रमेश दनोदिया, सूरजपुर नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवती राजवाड़े, कृष्णा गोयल बल्लू, मो. इस्माइल, वेद प्रकाश मिश्र, पार्षद चंदन सिंह, हर्ष दनोदिया, अनुपम फिलिप, प्रेमजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र यादव, सत्यम मिश्रा, दुर्गा गुप्ता, शनि मिश्रा, पवन अग्रवाल, गीतापुरी, रश्मि शर्मा, बीना शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में उत्कल समाज के अध्यक्ष सेनापति प्रधान, संजय पंडा, ऋषाथ देहुरी, सूरज कुमार सेठी, विद्याधर साहू, एसके स्वाई, फुल्ल नायक, अलंकार नायक, लक्ष्मी त्रिपाठी, संतोष सेठी, राजेंद्र प्रधान, अशोक स्वाई, गोविंद स्वाई, शितिकांत स्वाई, सुरेशन स्वाई, सुदर्शन सेठी, प्रभाकर स्वाई, विशाल स्वाई, प्रदीप त्रिपाठी, अखेय साहू, संतोष विश्वाल, निराकार नायक, पुरोहित सुशांत मिश्रा, सुभाष नायक, गीतांजलि स्वाई, ममता सेठी, दीप्ति स्वाई, सस्मिता साहू, अनुराधा प्रधान, अमूल्या नाहक, संगीता पांडा, छंदाश्री, मंजू स्वाई सहित अनेक स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाएं संभालीं।

उल्लेखनीय है कि कोयलांचल बिश्रामपुर में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का आयोजन पिछले दस वर्षों से लगातार किया जा रहा है। हर वर्ष इसकी भव्यता और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। पूरे नगर में दिनभर भक्तिभाव का वातावरण बना रहा।

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 3 पिकअप वाहनों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन के लिए सतत अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत आज विकासखंड शंकरगढ़ क्षेत्र में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान तीन पिकअप वाहनों में नियमों के विरुद्ध सवारियों का परिवहन करते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। एक पिकअप वाहन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि दो पिकअप वाहनों को शंकरगढ़ थाना में जप्त किया गया। और नियमानुसार 16 हजार रुपये का जुर्माना लिया गया जांच अभियान के दौरान कुल 21 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सभी पिकअप वाहन मालिकों एवं चालकों को सख्त हिदायत दी गई कि मालवाहक वाहनों में सवारियों का परिवहन न करें। ऐसा करना न केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

दो साल से अंधेरे में डूबा हाईवे, स्ट्रीट लाइट बंद होने से बढ़ा हादसों का खतरा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर दो वर्षों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें अब राहगीरों, वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। लगातार बढ़ते सड़क हादसों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर भाजयुमो पूर्व जिला महामंत्री दुर्गा गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत केशवनगर, सतपता अंतर्गत मधुवन होटल से एस्सार पेट्रोल पंप तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी स्ट्रीट लाइटें पिछले करीब दो वर्षों से खराब पड़ी हैं। रात होते ही पूरा मार्ग अंधेरे में डूब जाता है, जिससे इस व्यस्त हाईवे पर आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे के कारण इस मार्ग पर कई बार वाहन चालक सामने से आने वाले वाहनों, पैदल राहगीरों या

सड़क पर घूम रहे मवेशियों को समय रहते नहीं देख पाते, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। समय रहते स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण दिन-रात भारी वाहनों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों का आवागमन रहता है। रात के समय घना अंधेरा होने से महिलाओं को भी असुरक्षा और असहजता का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण लोगों में भय का माहौल बना रहता है। सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि आसपास के किसान भी इस समस्या से प्रभावित हैं। सड़क के दोनों ओर किसानों ने धान की फसल लगाई है। अंधेरे का फायदा उठाकर आवारा मवेशी खेतों में घुस जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि स्ट्रीट लाइटें चालू हो जाएं तो मवेशियों की आवाजाही पर भी काफी हद तक नियंत्रण रहेगा और फसल सुरक्षित रह सकेगी। पूर्व जिला महामंत्री दुर्गा गुप्ता ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और कई बार लोगों ने इसे उठाया है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने ग्रामीणों, किसानों और राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए स्ट्रीट लाइटों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की। कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई कर स्ट्रीट लाइटों को जल्द दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में केशवनगर सरपंच राजकुमार सिंह, गोविंद राय, राकेश यादव, वंशराज सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

8 वर्ष बाद जयनगर साइडिंग में लौटी रौनक, जल्द शुरू होगा रेलवे रैक से कोयला डिस्पैच

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। करीब 8 वर्षों से बंद पड़ी एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की जयनगर कोयला साइडिंग एक बार फिर गुलजार हो गई है। साइडिंग के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद अब एक-दो दिनों में रेलवे रैक उपलब्ध होते ही यहां से कोयले का डिस्पैच शुरू होने की संभावना है। वर्तमान में साइडिंग में लगभग 6 हजार टन कोयले का स्टॉक तैयार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार पहले बिश्रामपुर क्षेत्र में जयनगर और कुमदा दो प्रमुख कोल साइडिंग संचालित होती थी। क्षेत्र में कोयला उत्पादन घटने के बाद रेलवे रैक से कोयला भेजने का कार्य बंद कर दिया गया था। इसके बाद लंबे समय तक उपेक्षा के कारण जयनगर साइडिंग पूरी तरह वीरान हो गई। इस दौरान कबाड़ चोरों ने ओएचई तार, सीएचपी के तांबे और लोहे सहित करोड़ों रुपए की सामग्री चोरी कर ली, जिससे साइडिंग पूरी तरह निष्क्रिय हो गई थी। सूत्रों के अनुसार इस बीच भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न परिवहन के लिए साइडिंग के उपयोग का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप साइडिंग लगातार जर्जर होती चली गई। क्षेत्र की अमेरा, आमगांव, गायत्री और केतकी खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ने के बाद एसईसीएल ने जयनगर साइडिंग के पुनर्निर्माण के लिए करीब 41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। निर्माण एजेंसी राइट्स को कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुनर्निर्माण के बाद हाल ही में रेलवे अधिकारियों ने नई रेल लाइन का निरीक्षण किया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। इसके बाद साइडिंग में विभिन्न खदानों से कोयले की डंपिंग शुरू करा दी गई है। रेलवे से रैक की मांग भेज दी गई है और रैक मिलते ही कोयला डिस्पैच शुरू हो जाएगा। रेलवे रैक के माध्यम से एक बार में लगभग चार हजार टन कोयले का परिवहन किया जा सकता है, जबकि इतनी ही मात्रा के लिए सड़क मार्ग से 130 से अधिक ट्रकों की आवश्यकता पड़ती है। रैक से परिवहन होने पर सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा। सूत्रों का दावा है कि वर्षों तक रेलवे रैक से कोयला डिस्पैच बंद रहने के पीछे रोड सेल व्यवस्था को प्राथमिकता दिए जाने की भी चर्चा रही। सड़क मार्ग से कोयला परिवहन में अधिक संख्या में ट्रकों के संचालन के कारण अनियमितताओं और अवैध कमाई की आशंकाएं समय-समय पर उठती रही हैं। जयनगर साइडिंग के पुन: चालू होने के बाद एसईसीएल प्रबंधन द्वारा बंद पड़ी कुमदा साइडिंग के भी नवीनीकरण की दिशा में प्रस्ताव मंगाए जाने की जानकारी सामने आई है। यदि यह योजना भी अमल में आती है तो बिश्रामपुर क्षेत्र में रेलवे के माध्यम से कोयला परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

कोल कर्मचारियों का अनुकंपा नियुक्ति से लेकर मेडिकल और अलाउंस तक कई अहम फैसले

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। कोल इंडिया के लाखों गैर कार्यकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जेबीसीसीआई 11 की सातवीं बैठक के मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। बैठक में प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इनमें अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने, मेडिकल सुविधाओं के विस्तार, सेटलिंग-इन-अलाउंस में बढ़ोतरी, महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा कर्मियों की भर्ती, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरों की कमी दूर करने तथा नए लेबर कोड की तैयारी जैसे विषय प्रमुख रहे। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। आवेदन जमा करने की समय-सीमा, आवश्यक दस्तावेजों की जांच, मुख्यालय स्तर पर लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर सहमति बनी। इससे दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल अटेंडेंस रूल्स में संशोधन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उपचार सुविधाओं का दायरा बढ़ाने, गंभीर मरीजों के रेफरल मामलों को आसान बनाने तथा कर्मचारियों के आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया बैठक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक गैर कार्यकारी कर्मचारियों को 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने के प्रस्ताव पर सहमति रही। हालांकि यह बढ़ोतरी बोर्ड स्तर की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही लागू होगी। यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो नए स्थान पर पदस्थापना के दौरान कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सभी सहायक कंपनियों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। अलग शौचालयों की उपलब्धता, महिला कल्याण समितियों के गठन, विश्राम कक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की नियमित समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों में अब तक 501 आरओ प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। हालांकि ट्रेड यूनियनों ने कहा कि कई स्थानों पर ये प्लांट नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इनके रखरखाव, समय पर मरम्मत और गुणवत्ता की लगातार निगरानी की मांग उठाई।कोयला उद्योग में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरों की कमी को गंभीर विषय मानते हुए समिति ने योग्य कर्मचारियों को आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और प्रमाणपत्र हासिल करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। बैठक में प्रबंधन ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित चार नए लेबर कोड लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि ट्रेड यूनियनों ने स्पष्ट कहा कि जब तक सभी नियम पूरी तरह अधिसूचित नहीं हो जाते, तब तक किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए।

खनन नियमों में बड़ा बदलाव से मामूली गलती पर अब नहीं होगा आपराधिक केस

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। खनन और कोयला क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के लिए केंद्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। कोयला मंत्रालय ने खनन नियमों में व्यापक बदलाव का मसौदा जारी किया है, जिसके तहत अब छोटी प्रक्रियागत या तकनीकी त्रुटियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे मामलों में जेल या एफआईआर की जगह आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया जाएगा।

इस बदलाव से खनन क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं निजी कंपनियों के साथ-साथ निवेशकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में किए गए संशोधनों के अनुरूप खनिज रियायत नियम, 1960, खनिज अन्य संबंधित मामलों का नियंत्रण नियम 2004 तथा कोयला ब्लॉक आवंटन नियम 2017 में संशोधन का मसौदा सार्वजनिक किया है। इन प्रस्तावित संशोधनों पर राज्यों, कोयला कंपनियों, उद्योग संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से 21 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। सुझावों के परीक्षण के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्ताव है कि नए प्रावधान अगस्त 2026 से लागू किए जाएं। बताया जा रहा है है कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में नियमों को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है। इससे अनावश्यक कानूनी विवाद कम होंगे, प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश का माहौल बेहतर होने के साथ खनन परियोजनाओं के संचालन में भी सुविधा मिलेगी।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार यदि किसी खनन कंपनी या पट्टाधारी द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो सबसे पहले संबंधित अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। जवाब और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अधिकारी आदेश पारित करेंगे। यदि संबंधित पक्ष आदेश से संतुष्ट नहीं होता, तो उसे निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार भी मिलेगा। अब तक कई मामलों में नियमों के उल्लंघन पर सीधे एफआईआर दर्ज होने और आपराधिक मुकदमा चलने की संभावना रहती थी। प्रस्तावित संशोधन के बाद छोटी एवं प्रक्रियागत त्रुटियों को आपराधिक अपराध की श्रेणी से बाहर कर आर्थिक दंड के दायरे में लाया जाएगा। इससे कंपनियों को मामूली चूक के कारण लंबी कानूनी प्रक्रिया और आपराधिक मुकदमों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ निकली भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा

जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजायमान हुआ प्रतापपुर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर।जिले के प्रतापपुर में गुरुवार को भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा पूरे श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ निकाली गई। दूसरे वर्ष आयोजित इस ऐतिहासिक रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालू शामिल होकर नगर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। रथ यात्रा के दौरान पूरा प्रतापपुर ₹जय जगन्नाथ₹ के गगनभेदी जयघोष से गूंज उठा।

रथ यात्रा का शुभारंभ मां समलेश्वरी मंदिर प्रांगण से विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा की पूजा-अर्चना कर किया गया। इसके पश्चात सुसज्जित रथ नगर भ्रमण के लिए रवाना हुआ।रथ यात्रा प्रतापपुर के मुख्य चौक, बस स्टैंड, कॉलेज चौक, राजघराना चौक, कदमपारा चौक, थाना तहसील मार्ग सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर निकली। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की आरती उतारकर पुष्पवर्षा की तथा प्रसाद वितरित कर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों से निकलकर भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रथ यात्रा में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग एवं बच्चों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में उड़िया समाज के श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन, मृदंग, झांझ और ढोल की मधुर धुनों पर नृत्य करते हुए पूरे नगर को भक्तिरस में डुबो दिया। गाजे-बाजे और जयघोष के बीच निकली यह यात्रा प्रतापपुर के धार्मिक इतिहास का एक यादगार अध्याय बन गई। उल्लेखनीय है कि प्रतापपुर में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का आयोजन पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष दूसरे आयोजन में श्रद्धालुओं का उत्साह और भागीदारी पहले से कहीं अधिक देखने को मिली, जिससे यह आयोजन और भी भव्य एवं ऐतिहासिक बन गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा ओडिशा से प्रारंभ होकर आज पूरे भारत में आस्था का प्रतीक बन चुकी है। प्रतापपुर में भी इस परंपरा का विस्तार होने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और प्रसन्नता का माहौल है। आयोजकों के अनुसार रथ यात्रा 16 जून से प्रारंभ होकर 24 जून तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों एवं कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगी। इस दौरान भारी संख्या में नगर वासी सहित भक्त उपस्थित थे

पूरे नगर में दिनभर भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ से क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हुए रथ यात्रा को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दिया। इस दौरान संदीप रजक, अनुराग पटेल, शिवम गोयल, समर कश्यप, राहुल तिवारी, प्रियांशु सोनी, भुनेश्वर महाराज, रविशंकर भोय, राजेन्द्र प्रधान, अनिल गुप्ता, सन्यासी भोय, प्रदीप भोय, मोहन भोय, सुरेश सदप्रति, सन्तोष सोनी, सुरेश प्रधान, शिव प्रधान, संजय प्रधान, शुभम गुप्ता, विनय कश्यप, दक्ष मित्तल, अंकित मित्तल, आशीष पटेल, पूजन सिंह, विक्रम नामदेव सक्रिय थे।

साइबर अपराधों से बचाव हेतु प्रतापपुर पुलिस ने स्कूल में आयोजित की जागरूकता कार्यशाला

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अचीवर्स इंटरनेशनल स्कूल, प्रतापपुर में साइबर सिक्योरिटी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें नगर निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, ओटीपी एवं बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया सुरक्षा, डिजिटल भुगतान में सावधानियां तथा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी नई-नई तकनीकों का उपयोग कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को डिजिटल दुनिया में सतर्क और जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को देने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉ. राकेश मोहन मिश्रा, सुनील महापात्र, शिक्षक शिक्षिकाएं, पुलिस अधिकारी एवं जवान सहित बड़ी संख्या में अभिभावक व विद्यार्थियों मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थितो को साइबर सतर्कता एवं सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने की शपथ भी दिलाई गई तथा समाज में साइबर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया।

बिलासपुर में हर सातवें दिन हत्या,विधानसभा में चौंकाने वाले आंकड़े

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर ।छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर पेश किए गए आंकड़ों ने राज्य में बदलते अपराध के स्वरूप की तस्वीर सामने रख दी है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा साझा किए गए जिलेवार अपराध आंकड़ों के अनुसार, अब अपराध केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शांत और आदिवासी क्षेत्रों में भी हिंसक घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट से साफ संकेत मिलता है कि राज्य में अपराध का भूगोल तेजी से बदल रहा है और पुलिसिंग के पारंपरिक तरीके नई चुनौतियों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं।

बिलासपुर में हर सातवें दिन हत्या

न्यायधानी बिलासपुर अपराध के मामलों में राज्य के सबसे संवेदनशील जिलों में शामिल हो गया है। बीते दो वर्षों में जिले में 109 हत्या के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन हर सप्ताह एक हत्या हुई। इसी अवधि में 65 लूट और राहजनी की घटनाएं भी सामने आईं। विशेषज्ञों का मानना है कि शहर का तेजी से विस्तार, बाहरी क्षेत्रों में कमजोर निगरानी और बढ़ते भूमि विवाद अपराध बढ़ने की बड़ी वजह हैं।

जशपुर बना सबसे हिंसक जिला

सबसे चौंकाने वाले आंकड़े जशपुर जिले से सामने आए हैं। शांत और जनजातीय क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले जशपुर में पिछले दो वर्षों में 114 हत्याएं दर्ज की गईं, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं। यह आंकड़ा दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरी जिलों से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश और सामाजिक कारणों से हिंसक घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है।

दुर्ग में हत्या बढ़ी, लेकिन लूट घटी

दुर्ग जिले में हत्या के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले दो वर्षों में यहां 113 हत्या के मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस की कार्रवाई से लूट और डकैती के मामलों में करीब 37 प्रतिशत की कमी आई। लूट के मामले 43 से घटकर 27 रह गए।

बलौदाबाजार के हाईवे बने अपराधियों का निशाना

बलौदाबाजार जिले में हत्या के 67 मामले दर्ज हुए, लेकिन सबसे अधिक चिंता हाईवे पर बढ़ती लूटपाट को लेकर जताई गई। यहां लूट के मामलों की संख्या 15 से बढ़कर 35 पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगिक वाहनों की आवाजाही और सुनसान मार्गों का फायदा उठाकर गिरोह सक्रिय हैं।

कस्टडी में मौतों ने उठाए सवाल

विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार बीते दो वर्षों में धमतरी, कोरबा, बलरामपुर और बीजापुर जिलों में पुलिस हिरासत के दौरान चार लोगों की मौत हुई। इन घटनाओं ने पुलिस व्यवस्था, मानवाधिकारों और हिरासत प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

नक्सल प्रभावित जिले अपेक्षाकृत सुरक्षित

रिपोर्ट का एक सकारात्मक पक्ष यह भी सामने आया कि नक्सल प्रभावित जिले कई शहरी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहे। नारायणपुर जिले में दो वर्षों के दौरान हत्या और लूट समेत गंभीर अपराधों के कुल 43 मामले ही दर्ज हुए। इससे संकेत मिलता है कि जहां शहरों में संगठित अपराध और संपत्ति से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और पारिवारिक विवाद हिंसा का प्रमुख कारण बन रहे हैं।

पुलिसिंग के नए मॉडल की जरूरत

विधानसभा में पेश आंकड़ों से स्पष्ट है कि बदलते अपराध स्वरूप के बीच पारंपरिक पुलिस व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अपराध अब केवल शहरी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी कानून-व्यवस्था नई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में पुलिसिंग, खुफिया तंत्र और सामुदायिक निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

तहसीलदार के स्थगन आदेश के बावजूद मकान निर्माण का आरोप

कलेक्टर से शिकायत, कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। तहसीलदार के स्थगन आदेश के बावजूद जबरन मकान का निर्माण कराये जाने की शिकायत ग्रामीण ने कलेक्टर से करते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की है। जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम छिन्दिया निवासी बालेश्वर ने कलेक्टर को शिकायत पत्र में बताया है कि संयुक्त खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 2067, रकबा 0.1100 हेक्टेयर पर अनावेदक ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि जहां शिकायत करनी है कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामले को लेकर ग्रामीण ने पूर्व में तहसीलदार रामानुजनगर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर 11 जून को तहसीलदार ने स्थगन आदेश जारी करते हुए संबंधित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए थे। साथ ही अनावेदक को 16 जून को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। आदेश की प्रति थाना प्रभारी रामानुजनगर और संबंधित हल्का पटवारी को भी पालन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। ग्रामीण का आरोप है कि न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य लगातार जारी रखा गया और मकान का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना और राजस्व अमले द्वारा न्यायालय के आदेश का प्रभावी पालन नहीं कराया गया, जिससे अनावेदक का हौसला बुलन्द था और उसे निर्माण पूरा करने का अवसर मिल गया। ग्रामीण ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, न्यायालय के स्थगन आदेश की अवमानना करने वालों पर कार्रवाई करने, अवैध निर्माण हटाने तथा अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है। इस मामले में हल्का पटवारी अरविंद एक्का ने फोन के माध्यम से पूछे जाने पर कहा मामला न्यायालय में है ज्ञापन जारी होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। वही इस पूरे प्रकरण पर रामानुजनगर तहसीलदार से संपर्क का प्रयास किया गया मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाने की स्थिति में उनका पक्ष ज्ञात नहीं हो सका।

19 नदियों के संरक्षण को बनेगी कमेटी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर, । छत्तीसगढ़ से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल सूखने का कारण जानने और इन स्थलों को तलाशने के लिए राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश की 19 नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह कमेटी काम करेगी। चीफ सेक्रेटरी ने सभी चयनित मुख्य नदियों के उद्गम स्थल को चिन्हांकित कर सुरक्षित करने की बात बुधवार को हाईकोर्ट में कही। उन्होंने बताया कि विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत नदियों को संरक्षित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सभी नदियों और उनके उद्गम स्थल को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। बता दें, कि रिकॉर्ड में यह नदियां और उनके उद्गम स्थल फिलहाल नाले के रूप में दर्ज हैं। शासन द्वारा प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि 6 नदियों महानदी, हसदेव, तांदूला, पैरी, केलो, मांड के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद शासन ने कमेटी में इतिहासकार, लेखक, पर्यावरणविद को भी शामिल किया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अरपा में सालभर पानी की योजना के साथ प्रदेश की 11 प्रमुख नदियों के रिवाइवल की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार ने इस बात पर भी सहमति जताई कि नई कमेटी गठित कर नदियों के स्रोतों की पहचान और संरचना सुनिश्चित की जाएगी। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार नदियों के उदगम स्थल के संरक्षण की बात तो कर रही है लेकिन इसके बाद आगे 2 किलोमीटर क्षेत्र तक के प्राकृतिक प्रवाह पर ध्यान नहीं है। इन क्षेत्रों में कब्जा करते हुए खेती हो रही है। इसे भी संरक्षित करना होगा। कहीं कोई निजी जमीन है तो उसका अधिग्रहण सरकार को करना होगा, कब्जे हटाने होंगे। इसके बाद ही नदियों का प्रवाह बेहतर हो सकेगा। हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए सरकार को इस तरफ ध्यान देने कहा है।

राघवेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के बयान का दिया हवाला, संस्कृति मंत्री ने अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई का दिया भरोसा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

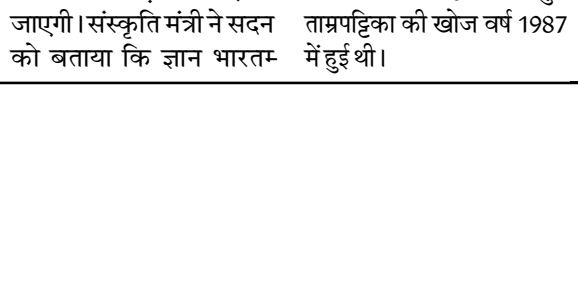

रायपुर ।छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को ज्ञान भारतम्-अभियान के तहत प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ताम्रपत्रों के सत्यापन का मुद्दा सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने मल्हार से प्राप्त ऐतिहासिक बालार्जुन ताम्रपट्टिका की भाषा और लिपि को लेकर सरकार से सवाल किए, जिस पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान राघवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम ह्यमन की बातज्में देश को बताया था कि यह ऐतिहासिक ताम्रपत्र ब्राह्मी और पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि विभागीय मंत्री ने सदन में इसे ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा होना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर मंत्री से भ्रामक जवाब दिलवाया है, जिससे सदन और देश को गुमराह किया गया है। कांग्रेस विधायक ने मांग की कि सदन को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। विपक्ष के सवालों के बीच संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने मामले की गंभीरता स्वीकार करते हुए कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा तथ्यात्मक त्रुटि की गई है तो पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संस्कृति मंत्री ने सदन को बताया कि ज्ञान भारतम् अभियान के तहत छत्तीसगढ़ से मोबाइल ऐप के माध्यम से कुल 1,24,422 पांडुलिपियों का पंजीयन किया गया था। इनमें से 12,040 पांडुलिपियों का सत्यापन ज्ञान भारतम् केंद्र, नई दिल्ली द्वारा किया गया है, जबकि 1,12,382 पांडुलिपियां तकनीकी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत हुई हैं। मंत्री ने बताया कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक स्थल मल्हार से प्राप्त प्रसिद्ध बालार्जुन ताम्रपट्टिका की खोज वर्ष 1987 में हुई थी।

उप-पंजीयक कार्यालय के पीछे शराब की खाली बोतलों का अंबार, जिम्मेदारों की नाक के नीचे 'नशे का अड्डा'

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर।यहां जिला मुख्यालय का एक ऐसा कार्यालय जहां से प्रतिदिन शासन को लाखों का राजस्व मिलता है, वह खुद अपनी दुर्दशा और प्रशासनिक अनदेखी पर आंसू बहा रहा है। हम बात कर रहे हैं यहां के उप-पंजीयक कार्यालय की। जहां दूर-दराज के ब्लॉकों और गांवों से अपनी जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने आने वाले सीधे-साधे ग्रामीणों को क्या पता कि जिस दफ्तर में वे अपनी गाढ़ी कमाई लेकर आ रहे हैं, वहां अपराधियों और नशेड़ियों का गढ़ बन चुका है।

दफ्तर के पीछे 'मधुशाला सा दृश्य

कार्यालय के पूछे से जो तस्वीरें सामने आई हैं वह पूरे सिस्टम को शर्मसार करने के लिए काफी है। कार्यालय के ठीक पीछे बड़ी मात्रा में देशी विदेशी शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी हैं। नजारा देखकर सहजता से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ढलती शाम के साथ ही इस सरकारी परिसर को शराबियों के ठिकाने में तब्दील कर दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि अफसरों की नाक के नीचे लंबे समय से यह खेल चल रहा है, लेकिन सम्बंधित जिम्मेदार धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते बैठे हैं।

शौचालय के आभाव में टूटे कांच के बीच झाड़ियों में जाना मजबूरी

प्रतिदिन लाखो का राजस्व देने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यालय में शहर सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते है जिनमे महिलाएं भी शामिल है। जिनके लिए बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। दफ्तर में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। लम्बा सफर तय कर यहां आए ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को शौच या पेशाब के लिए जाना होता है, तो उन्हें लाचारी में कार्यालय के पीछे की झाड़ियों का रुख करना पड़ता है। जहाँ नशेड़ियों द्वारा उपयोग के बाद शराब की खाली बोतलों को वहीं फोड़ कर फेंक दिया जाता है। बरसात के इस मौसम में हरी घास और कीचड़ के बीच कांच के ये नुकीले टुकड़े छिपे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई ग्रामीण वहां जाता है, तो किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। कांच पैर में धंसने से गंभीर संक्रमण या गहरी चोट का खतरा हर पल मंडरा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा

एक तरफ सरकार स्वच्छता का ढिंढोरा पीटती है, वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय के इस महत्वपूर्ण कार्यालय परिसर में साफ-सफाई का नामोनिशान नहीं है। बड़ी बड़ी झाड़ियां, कचरे का ढेर और चारों तरफ गंदगी का अंबार इस कार्यालय की पहचान बन गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कमरों में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं और उन्हें जनता की सहूलियत व दफ्तर की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। क्या जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग के जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी परिसर में शराबखोरी करने वाले इन असामाजिक तत्वों पर आखिर कार्रवाई औ दूर-दराज से आने वालो को बुनियादी शौचालय की सुविधा कब मिलेगी। सब देखते हुए भी घृतराष्ट्र बने जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे।

सम्पादकीय

कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और अवसरों का सेतु भी है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत लागू की गई त्रि-भाषा नीति (थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला) भी इसी सोच पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की इस नीति पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। अदालत की यह टिप्पणी शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को रेखांकित करती है, लेकिन यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या इस नीति को लागू करने के लिए देश का शिक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना है। नई व्यवस्था के अनुसार नौवीं और दसवीं कक्षा में तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। इससे विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा और देश की भाषाई विविधता से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह कदम भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस नीति को लेकर कई व्यावहारिक चिंताएं भी सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि अनेक विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से फ्रेंच, जर्मन या अन्य विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं। ऐसे छात्रों के लिए अचानक नई भारतीय भाषा अपनाना आसान नहीं होगा। इससे उनकी पढ़ाई और परीक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं। दूसरी ओर, कई स्कूलों में संबंधित भाषाओं के प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। अनेक भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें भी समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए सीबीएसई ने अपनी प्रारंभिक व्यवस्था में संशोधन किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान दसवीं, नौवीं, आठवीं और सातवीं के विद्यार्थियों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। केवल वर्तमान छठी कक्षा के विद्यार्थी पहले ऐसे बैच होंगे, जिन पर यह नीति पूरी तरह लागू होगी। यह निर्णय बताता है कि सरकार भी चरणबद्ध तरीके से इस बदलाव को लागू करना चाहती है, ताकि विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। वहीं जो छात्र शैक्षणिक वर्ष 2027-28 में कक्षा 10वीं में प्रवेश करेंगे, उन्हें अपनी तीसरी भाषा (जिसे आर3 कहा गया है) का स्कूल-आधारित इंटरनल असेसमेंट पास करना ही होगा। इसके बिना उन्हें सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। दरअसल, भाषा सीखने के अनेक लाभ हैं। शोध बताते हैं कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की स्मरण शक्ति, तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच को विकसित करता है। भविष्य में रोजगार, उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए नई भाषा सीखना कभी नुकसान का सौदा नहीं हो सकता। यदि पर्याप्त शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें, डिजिटल सामग्री और प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं होगा तो अच्छी मंशा वाली नीति भी विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भाषा नीति लागू करने से पहले सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों और विद्यार्थियों को बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिले। बहुभाषी भारत में भारतीय भाषाओं को सम्मान मिलना समय की मांग भी है। यदि यही संतुलन बनाए रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी वास्तव में सार्थक सिद्ध होगी कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता।

आर्थिकी

ममता कुशवाहा

महंगाई : अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौती

> जून माह में खुदरा महंगाई बढ़कर लगभग 4 .38 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला कि महंगाई का दबाव फिर से बढ़ रहा है। लगातार कई महीनों की वृद्धि ने भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिक–सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, महंगाई का यह बढ़ता दबाव केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि हर घर की रसोई, हर किसान की खेती, हर व्यापारी के कारोबार और हर युवा के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। यही कारण है कि बढ़ती महंगाई को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है।

कुछ दिन पहले जारी हुए खुदरा महंगाई के ताज़ा आंकड़ों ने एक बार फिर देश में आर्थिक बहस को तेज कर दिया है। जून माह में खुदरा महंगाई बढ़कर लगभग 4.38 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद यह स्पष्ट संकेत मिला कि महंगाई का दबाव फिर से बढ़ रहा है। लगातार कई महीनों की वृद्धि ने भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिक-सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे समय में जब भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, महंगाई का यह बढ़ता दबाव केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि हर घर की रसोई, हर किसान की खेती, हर व्यापारी के कारोबार और हर युवा के भविष्य से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। यही कारण है कि बढ़ती महंगाई को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और विकासात्मक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है।

महंगाई का सामान्य अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से है। जब किसी परिवार को पहले की तुलना में समान वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है, तब उसकी क्रय शक्ति घटने लगती है। यदि आय उसी गति से नहीं बढ़ती, जिस गति से महंगाई बढ़ रही हो, तो जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि महंगाई का सबसे अधिक बोझ मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है। इनके बजट का बड़ा हिस्सा भोजन, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक जरूरतों पर खर्च होता है, इसलिए कीमतों में मामूली वृद्धि भी उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर देती है। वर्तमान समय में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़े हैं। इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर हर परिवार की रसोई पर पड़ता है। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी सीमित आय पर निर्भर है, वहां खाद्य महंगाई केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक चिंता का विषय बन जाती है। भोजन महंगा होने पर परिवार अपनी आवश्यकताओं में कटौती करने को मजबूर होते हैं, जिससे पोषण स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। महंगाई को बढ़ाने वाले कारण केवल घरेलू नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है, तो परिवहन लागत बढ़ती है। इसका प्रभाव उद्योगों की उत्पादन लागत पर पड़ता है और अंततः उपभोक्ताओं को वस्तुएं महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। इस प्रकार वैश्विक घटनाओं का असर सीधे भारतीय बाजार और आम नागरिक के जीवन पर दिखाई देता है। जलवायु परिवर्तन भी महंगाई का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं। यदि फसलें खराब होती हैं या उत्पादन कम होता है, तो बाजार में आपूर्ति घट जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत की बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, इसलिए मौसम की अनिश्चितता केवल किसानों की आय

ही नहीं, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता को प्रभावित करती है। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अधिक गंभीर हो सकते हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र को अधिक सक्षम और तकनीक आधारित बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा प्रभाव देश की मौद्रिक नीति पर पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को संतुलित रखना है। यदि महंगाई लगातार लक्ष्य से ऊपर बनी रहती है, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। रेपो रेट बढ़ने का अर्थ है कि बैंकों को धन महंगा मिलेगा, जिसका असर गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और उद्योगों को मिलने वाले कर्ज पर पड़ेगा। ब्याज दरें बढ़ने से लोग कम खर्च करते हैं और उद्योग भी निवेश में सावधानी बरतते हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी हो सकती है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण और विकास के बीच संतुलन बनाना केंद्रीय बैंक के लिए सबसे कठिन जिम्मेदारी होती है। महंगाई का प्रभाव केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहता। उद्योगों के लिए कच्चा माल, बिजली, ईंधन और परिवहन महंगा होने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। यदि कंपनियां बढ़ी हुई लागत उपभोक्ताओं पर डालती हैं, तो वस्तुएं और महंगी हो जाती हैं। यदि वे कीमतें नहीं बढ़ातीं, तो उनका लाभ घटता है और निवेश प्रभावित होता है। इसका असर रोजगार सृजन पर भी पड़ सकता है। छोटे और मध्यम उद्योग, जिनकी आर्थिक क्षमता सीमित होती है, ऐसे समय में सबसे अधिक दबाव महसूस करते हैं। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की विकास दर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार के सामने भी इस समय अनेक चुनौतियां हैं। केवल ब्याज दरों के सहारे महंगाई पर स्थायी नियंत्रण संभव नहीं है। इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करना, जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा कृषि और परिवहन क्षेत्र में सुधार करना आवश्यक है। आवश्यक वस्तुओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, भंडारण क्षमता बढ़ाना और किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना भी महंगाई नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर आयातित ईंधन पर निर्भरता कम की जा सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था आज पहले की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक हो चुकी है। इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्से में उत्पन्न आर्थिक या राजनीतिक संकट का प्रभाव भारतीय बाजार तक पहुंच जाता है। ऐसे में आर्थिक नीतियों को केवल वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि भविष्य के संभावित जोखिमों को देखते हुए तैयार करना होगा। मूल्य स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को एक साथ लेकर चलना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार, रिजर्व बैंक, उद्योग जगत और किसानों के बीच बेहतर समन्वय ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान दे सकता है। वास्तव में बढ़ती महंगाई केवल कीमतों का प्रश्न नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता, सामाजिक संतुलन और विकास की दिशा से जुड़ा हुआ विषय है। यदि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाएं, तो इस चुनौती को अवसर में भी बदला जा सकता है। मजबूत कृषि व्यवस्था, पारदर्शी बाजार, संतुलित मौद्रिक नीति, बेहतर आपूर्ति तंत्र और दूरदर्शी आर्थिक निर्णय ही भारत को महंगाई के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। आज आवश्यकता आंकड़ों पर बहस करने से अधिक ठोस और समन्वित कार्रवाई की है, ताकि आर्थिक विकास की गति भी बनी रहे और आम नागरिक की थाली तथा जेब दोनों सुरक्षित रह सकें।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संघर्ष

डॉ. घनश्याम बादल

होर्मुज़ पर टैक्स की जंग

समुद्र पर किसका अधिकार

युद्ध केवल मोर्चों पर नहीं लड़े जाते, वे समुद्रों, व्यापार मार्गों, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर भी लड़े जाते हैं। आज फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार, हार्मुज़ जलडमरूमध्य, इसी प्रकार के संघर्ष का केंद्र बन गया है। ईरान और अमेरिका एक-दूसरे पर युद्धविराम की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। एक ओर ईरान अपने समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण और शुल्क लगाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका भी समुद्री सुरक्षा के नाम पर जहाजों से 20 प्रतिशत शुल्क वसूलने की घोषणा कर चुका है। दोनों पक्ष अपने-अपने कदम को वैध ठहरा रहे हैं, किंतु प्रश्न यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा? उत्तर स्पष्ट है-दुनिया। ताज़ा घटनाक्रम में दोनों देश युद्धविराम के उल्लंघन के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने हार्मुज़ में जहाजों की आवाजाही बाधित कर समझौते की भावना का उल्लंघन किया, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, नाकेबंदी और इज़राइल को समर्थन ने युद्धविराम को अर्थहीन बना दिया। स्वतंत्र रूप से इन दावों की पूरी पुष्टि संभव नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोनों पक्ष युद्धविराम की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं और यही टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इस पूरे संकट में इज़राइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ईरान का आरोप है कि इज़राइल की सैन्य गतिविधियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है, जबकि अमेरिका इसे क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रश्न बताता है। परिणाम यह है कि युद्ध केवल ईरान और अमेरिका के बीच सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया उसकी चपेट में आ गया है। हार्मुज़ विश्व ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा है। सामान्य परिस्थितियों में विश्व के समुद्री तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। यदि इस मार्ग पर कोई भी पक्ष कर लगाए, जहाजों को रोकें या सैन्य नियंत्रण स्थापित करें, तो उसका प्रभाव केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, समुद्री बीमा महंगा होगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और अंततः पूरी दुनिया में महंगाई का दबाव बढ़ेगा। सबसे रोचक और विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि दोनों पक्ष लगभग एक जैसी नीति अपना रहे हैं। ईरान कहता है कि वह अपनी समुद्री सीमा और सुरक्षा के लिए शुल्क लेगा। अमेरिका कहता है कि वह समुद्री सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है, इसलिए उसके लिए भी शुल्क लिया जाना चाहिए। नाम अलग-अलग हो सकते हैं-'टैक्स', 'टोल', 'सुरक्षा शुल्क' या 'प्रतिपूर्ति'-लेकिन अंततः भुगतान जहाज मालिकों को करना होगा और उसका भार दुनिया के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का मूल सिद्धांत यह है कि अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों पर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाए। किसी एक देश द्वारा समुद्री मार्ग को आर्थिक या राजनीतिक दबाव का साधन बनाना वैश्विक व्यापार व्यवस्था की भावना के विरुद्ध माना जाता है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के दावों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न उठ रहे हैं। भारत के लिए यह संकट विशेष चिंता का विषय है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग आयात करता है और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। यदि हार्मुज़ में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल और डीज़ल महंगे होंगे, परिवहन लागत बढ़ेगी, उर्वरकों की कीमत प्रभावित होगी और अंततः महंगाई का दबाव आम नागरिक तक पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा और भारतीय निर्यात-आयात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खाड़ी देशों की स्थिति भी कम कठिन नहीं है। वे एक ओर अमेरिका के सुरक्षा सहयोगी हैं, दूसरी ओर उनकी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात पर निर्भर है। इसलिए वे किसी भी ऐसे संघर्ष से बचना चाहते हैं जिससे व्यापार बाधित हो। लंबे समय तक तनाव बना रहा तो खाड़ी देशों की आर्थिक वृद्धि और निवेश दोनों प्रभावित होंगे। वास्तविकता यह है कि आधुनिक युद्धों में 'आर-पार की जीत' अब लगभग असंभव हो गई है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी ईरान जैसे क्षेत्रीय शक्ति-संपन्न देश को स्थायी रूप से झुका नहीं सकती, और ईरान भी अमेरिका को सैन्य रूप से पराजित करने की स्थिति में नहीं है। यह संघर्ष किसी एक क्षेत्र का नहीं, पूरी मानवता का प्रश्न बन चुका है। यदि अमेरिका और ईरान वास्तव में शांति चाहते हैं तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि प्रतिष्ठा की लड़ाई में आर्थिक स्थिरता और वैश्विक विश्वास को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। आधुनिक विश्व में स्थायी विजय युद्ध से नहीं, संवाद और संतुलित कूटनीति से ही प्राप्त होती है।

बुरे लोग ही दूसरों में ढूंढ़ते हैं दोष

लोग प्रायः दूसरों में दोष ढूंढ़ने में लगे रहते हैं। इसी को छिद्रान्वेषण कहते हैं। ऐसा करने वाले लोग अपने बड़े-बड़े दोषों को देखते हुए भी नहीं देख पाते। फिर भी दूसरों में दोष निकालने से बाज नहीं आते। यह प्रवृत्ति न केवल स्वयं के लिए, अपितु समाज के लिए भी घातक है। इसी कारण समाज में ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का परिवेश बनता है। इसका सर्वाधिक विपरीत प्रभाव उन लोगों के मनोबल पर पड़ता है, जो ईमानदारी से समाज और देश की सेवा कर जीवन यापन करना चाहते हैं। छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति अमूमन उन्हीं लोगों में देखने को मिलती है जो स्वयं बुराइयों के भंडार होते हैं। इससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर क्षरण होता है और स्वयं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, 'मनुष्य की यह प्रवृत्ति कभी अपने भीतर सद्गुणों का विकास नहीं होने देती।' परिणामस्वरूप मन, वाणी और कर्म तीनों कलुषित हो जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन छिद्रान्वेषी दुष्प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने कभी अपने दोष देखने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए उसके मन, वाणी और कर्म सभी कलुषित हो गए। एक बार गुरु द्रोण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को राज्य में साधु पुरुषों की गणना के लिए भेजा तो दुर्योधन को कोई साधु पुरुष मिला ही नहीं। यह दुर्योधन की छिद्रान्वेषी दुष्प्रवृत्ति का परिणाम था। इसके विपरीत युधिष्ठिर को कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। वास्तव में दूसरे के दोष देखने का अधिकार उसी को है, जिसमें वह बुराई न हो।

संकलित

दर्शन

झूठ बोलकर मिला ज्ञान ज्यादा दिन नहीं चलता

परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, योद्धा और गुरु हैं। महाभारत के समय भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण इनके शिष्य थे। परशुराम जी से ज्ञान हासिल करने के लिए कर्ण ने झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, क्योंकि उस समय परशुराम जी ब्राह्मणों को ही ज्ञान दे रहे थे। कर्ण परशुराम जी का शिष्य बन गया और ज्ञान हासिल करने लगा।

एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय कर्ण की जांघ पर एक बड़े कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद न टूटे ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं जगाया। नींद से जागने पर जब परशुराम ने देखा कि कर्ण के पैर से खून बह रहा है तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है। तब परशुराम ने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दिया था कि मेरी सिखाई हुई विद्या की जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। महाभारत युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना-सामना हुआ, उस समय कर्ण अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट करने की विधि भूल गए थे। इसके बाद अर्जुन ने श्रीकृष्ण के कहने पर कर्ण का वध कर दिया। झूठ बोलकर हासिल की गई विद्या लंबे समय तक साथ नहीं देती है। ज्ञान सीखने के लिए त्याग और तप दोनों ही करना पड़ता है तब कहीं सही मायनों में ज्ञान अर्जित हो पाता है। दूसरा, सही गुरु का मिलना भी जरूरी है अन्यथा भटकते रहना पड़ता है।

संकलित

प्रेरणा

सटाका

आज की पाती

होर्मुज संकट : विश्व आर्थिकी के लिए बढ़ता खतरा

अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। यदि यह समुद्री मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार व्यवस्था प्रभावित होगी। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय संघर्ष अब वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। प्रतिदिन दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। जहाजों की आवाजाही अगर बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आना स्वाभाविक है। - *कमलेश शर्मा, अंबाला*

ट्रेंड

अदम्य कौशल की प्रतीक बनीं महिला क्रिकेट

भारतीय महिला क्रिकेट के एक नए दौर की शुरुआत। इंग्लैंड के खिलाफ आज का टेस्ट मैच जीतने के लिए हमारी महिला क्रिकेट टीम को बधाई। यह भारतीय महिला क्रिकेट के अदम्य कौशल का प्रतीक है।

- **अमित शाह,** केंद्रीय गृहमंत्री

डबल-इंजन' सरकार

भारत सरकार पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कसर नही छोड़ेगी। 'डबल-इंजन' सरकार कदम-से-कदम मिलाकर और कंधे-से-कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल को तरक्की और विकास के मामले में देश में नंबर वन बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी।

-**शिवराज सिंह चौहान,** केंद्रीय कृषि मंत्री

शिक्षा व्यवस्था बनी वसूली का जरिया

भ्रष्ट, अन्यायपूर्ण, पक्षपाती और बेईमान - ये चार शब्द मेरे नहीं है, बल्कि देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सच तो यह है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब जबरन वसूली का एक बेईमान जरिया बन गई है।

- **राहुल गांधी,** सांसद, कांग्रेस

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को समर्थन

सीजेपी का जंतर-मंतर पर कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। सोनम वांगचुक वहां कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

-**अरविंद केजरीवाल,** पूर्व सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

यूरोप में भीषण गर्मी भौंरों के लिए साबित हो रही जानलेवा

संभव है कि गर्मियों के महीनों में आपको अपने आस-पास फुटपाथ पर मरे हुए भौंरे (बम्बलबीज) दिखाई दें। इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें कुछ मौसमी और काफी हद तक इंसानी गतिविधियां हैं। भौंरे सामाजिक होते हैं और कॉलोनियों में रहते हैं। इन कॉलोनियों को बहुत सक्रिय मजदूर भौंरें चलाते हैं, जिनकी उम्र बहुत छोटी यानी चार से छह हफ्ते की होती है। इसका अभिप्राय है कि काफ़ी कम समय में ही बूढ़े होकर ये भौंरें मर जाते हैं और कॉलोनी में बीमारी फैलने से रोकने के लिए, स्वस्थ युवा मजदूर भौंरे मरे हुए भौंरों को बाहर निकालकर कॉलोनी से काफ़ी दूर ले जाते हैं। एक और वजह मौसम है। 2026 में इंग्लैंड में जून का महीना अब तक का सबसे गर्म रहा (और पूरे ब्रिटेन के लिए यह दूसरा सबसे गर्म महीना था) और इस गर्मी में तापमान के और भी ज्यादा रहने की आशंका है। इस तरह की अत्यधिक गर्मी से भौंरों में तनाव पैदा होता है। लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से उनके विकास पर असर पड़ता है और उनकी आबादी की लंबे समय की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। भीषण गर्मी का नकारात्मक असर इन भौंरों के प्रजनन, उड़ने और भोजन की तलाश करने की क्षमता पर भी पड़ता है।

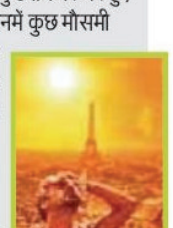

ऑफ बीट

साइकिल चलाना पैदल चलने से चार गुना ज्यादा प्रभावी

साइकिलिंग के माध्यम से लोग चलने या दौड़ने की तुलना में कम ऊर्जा खपत पर तेज और दूर तक सुविधाजनक तरीके से सफर करने में सक्षम होते हैं।

लेकिन आखिर पैदल चलने की तुलना में साइकिलिंग इतनी आसान क्यों लगती है? इसका जवाब छिपा है उस सुव्यवस्थित जैव-यांत्रिकी में जो साइकिल का हमारे शरीर के साथ तालमेल बनाती है। लेकिन यह सरलता एक ऐसी इंजीनियरिंग को छिपाए हुए है, जो मानव शरीर की संरचना और क्रिया प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। जब हम चलते या दौड़ते हैं तो असल में हमारा झुकाव एक नियंत्रित तरीके से आगे की ओर रहता है और हर कदम पर खुद को संभालते हैं। हमारे पैरों को हर कदम पर एक बड़े दायरे में आगे बढ़ाना पड़ता है, हर कदम पर पैरों को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठाना पड़ता है। सिर्फ इस क्रिया में ही शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। साइकिल पर, आपके पैर बहुत छोटी गोलाकार गति में घूमते हैं। हर क्रिया पर अपने पूरे पैर का वजन उठाने के बजाय, आप बस अपनी जांघों और पिंडलियों को एक संकुचित पैडल वाली साइकिल पर घुमाते हैं। इस वजह से शारीरिक ऊर्जा की बचत तुरंत महसूस होती है। लेकिन असली दक्षता यह है कि मानव ताकत ऐसी ऊर्जा में बदल जाती है जो साइकिल को आगे बढ़ाती है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए

एनएच-19 ,वाराणसी रिंग रोड के बीच 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर से लाखों लोगों को होगा लाभ, समय बचेगा

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वैष्णव ने दी जानकारी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) और औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाई देने के लिए अब तक के सबसे बड़े निवेश प्रस्तावों में से एक को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई युगांतकारी निर्णय लिए गए, जिनकी घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। देश को वैश्विक विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) हब बनाने और कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने कुल 2,19,353 करोड़ के कुल बजट वाले सा बड़े प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। यह विशाल पैकेज देश की आर्थिक विकास दर को तेज करने और औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने एनएच-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 14,447.64 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है।

2,19,353 करोड़ की परियोजना स्वीकृत

एनएच-19 उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता (डंकुनी) तक जाता है। यह लगभग 1323 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 2,19,353 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

यातायात होगा सुगम,जाम से मुक्ति मिलेगी

गंगा नदी के किनारे छह लेन का कॉरिडोर: वाराणसी में भीड़ कम करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने एनएच-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच गंगा नदी के किनारे कनेक्टिविटी के साथ एक लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है। 46.039 किमी लंबी इस परियोजना में 6 लेन का एलिवेटेड मेन कैरिजवे, एक प्रतिष्ठित केबल-स्टे ब्रिज, एक्स्ट्राडोज्ड फुट ओवर ब्रिज-कम-मेजर ब्रिज, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड शामिल हैं। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएम) के तहत कुल 14,447.64 करोड़ की पूंजी लागत पर अमल में लाई जाएगी।

वरुणा के किनारे कॉरिडोर

वाराणसी में यातायात जाम कम करने के लिए, वरुणा नदी के किनारे एनएत -31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किमी लंबे लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दे दी है। इसमें मुख्य कैरिजवे, फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड सहित 6/4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत 10,998.32 करोड़ से बनाया जाएगा।

ओडिशा-झारखंड की 2 रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी, 145 किमी बढ़ेगा रेल नेटवर्क

बैठक में रेलवे मंत्रालय की दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इनकी कुल अनुमानित लागत 3,907 करोड़ है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें पारादीप-हरिदासपुर रेल लाइन का दोहरीकरणऔर राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। ओडिशा और झारखंड के चार जिलों में भारतीय रेलवे नेटवर्क का करीब 145 किलोमीटर विस्तार होगा। इससे रेल मार्ग की क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारु होगा और माल एवं यात्री परिवहन में सुधार आएगा।

नई राष्ट्रीय निवेश नीति भी बनाई

कैबिनेट ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दे दी। उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तुत इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में गैस-आधारित नई यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना को आकर्षित करना है, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता कम हो।

नीति के प्रमुख फायदे

- पारदर्शिता बढ़ेगी: निश्चित और परिवर्तनशील लागतों को अलग-अलग किया जाएगा।
- व्यावहारिक रिटर्न: इक्विटी पर रिटर्न के लिए 12% न्यूनतम और 16% अधिकतम सीमा तय।
- विदेशी मुद्रा जोखिम कम: चार साल बाद निश्चित लागत को रुपये में बदलने का प्रावधान।
- बड़ी बचत: प्रत्येक नए संयंत्र पर 250 करोड़ से अधिक की बचत होने का अनुमान।

सेमीकॉन 2.0 मिशन को मंजूरी

वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 1.27 लाख करोड़ के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या सेमीकॉन 2.0 मिशन के दूसरे एडिशन को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने चिप बनाने को बढ़ावा देने के साथ-साथ, मोबाइल पीएलआई स्कीम को बढ़ाने देने की भी घोषणा की।

62,500 करोड़ की एमपीएमएस योजना को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। 62,500 करोड़ के बजट वाली यह योजना भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ाने, घरेलू स्तर पर अधिक पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने, सप्लाई चेन मजबूत करने और भारतीय मोबाइल ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी।

ममता का बागियों को संदेश

अभिषेक बेनर्जी के हाथों में ही रहेगी टीएमसी की कमान

कोलकाता। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री

ममता बेनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनके भतीजे अभिषेक बेनर्जी ही भविष्य में पार्टी के नेता बनेंगे। उन्होंने बुधवार को वीडियो बयान जारी करके राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। मदन मित्रा और सुदीप बंद्योपाध्याय जैसे दिग्गज नेताओं के द्वारा अभिषेक पर निशाना साधे जाने के बाद ममता का यह वीडियो बागी नेताओं को स्पष्ट संदेश दे रहा है।

गद्दारों की ओर से मैं जनता से माफी मांगती हूं

ममता ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को 'गद्दार' करार दिया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के जिन गद्दारों ने अपने निजी हितों के लिए इस कठिन समय में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, मैं उनकी ओर से बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। कुछ लोग केंद्रीय एजेंसियों के डर से या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी को धोखा दे रहे हैं।

आवाज का नमूना देने कोर्ट पहुंचे अभिषेक

सांसद अभिषेक बेनर्जी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित धमकी भरे भाषण

से जुड़े मामले में बुधवार को विधाननगर एसडीजेएम (सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) अदालत में अपना आवाज का नमूना (वॉयस सैंपल) दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बेनर्जी दोपहर में अदालत पहुंचे और करीब डेढ़ घंटे तक वहां मौजूद रहे।

हिंदुआरी में बनेगी आत्मनिर्भर वृहद गौशाला

सोनभद्र। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सोनभद्र जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने नई हिंदुआरी में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड से एक आत्मनिर्भर वृहद गौशाला के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना पर 1 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत आएगी तथा निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा।

एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक शक्तिनगर सत्येन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत थाना शक्तिनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा

रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गणेश सिंह आ०/पति स्व० गोपाल सिंह जाति क्षत्रीय, निवासी डी०सी० रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा मोहल्ला-महावीर वार्ड, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1893/4777/10 रकबा 0.02 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 20/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा आ.स्व. नागेश्वर प्रसाद, उम्र 70 वर्ष, सतेन्द्र कुमार कुशवाहा आ.स्व. नागेश्वर प्रसाद, उम्र 54 वर्ष, दोनों निवासी मोहल्ला बाबूपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक एवं अनावेदकगण विरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्रीमती चन्द्रावती देवी, श्रीमती विमला कुशवाहा आ.स्व. नागेश्वर प्रसाद, सभी निवासी अम्बिकापुर के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ०पुर, शीट नं. 03 मोहल्ला बाबूपारा स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3531/23 रकबा 0.07 1/2 एकड़ भूमि है। उक्त भूखण्ड में से अनावेदकगण द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध हकत्याग विलेख दिनांक 21.04.2026 का निष्पादन आवेदकगण के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध हकत्याग विलेख के आधार पर आवेदकगण द्वारा उक्त आवेदित भूमि का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध पंजीबद्ध हकत्याग की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 29/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक- 14/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

शपथपत्र

मैं सुनील पटेल पिता स्व जयश्रीराम पटेल लगभग 50 वर्ष जाति कुनबी निवासी ग्राम कैलाशपुर तहसील चलगली जिला बलरामपुर छ०ग० का मुल निवासी होकर निम्नाकित शपथ पुर्वक कथन करती हूँ कि-

मैं शपथ पुर्वक कथन करती हूँ कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र व अंकसूची मे बालन्दराज पटेल पिता सुनील पटेल अग्रेजी में (Balandraj patel) तथा जन्म तिथि दिनांक 30/07/2012 अंकित है जो सही है तथा आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम बालंद अग्रेजी में (Balond) तथा जन्म तिथि 01/01/2012 त्रुटि वश दर्ज हो गया है। जो गलत है।

मैं शपथ पुर्वक कथन करती हूँ कि मेरे पुत्र का नाम बालंद अग्रेजी में (Balond) के स्थान पर बालन्दराज पटेल पिता सुनील पटेल अग्रेजी में (Balandraj patel) तथा जन्म तिथि 30/07/2012 जन्म प्रमाण पत्र व अंकुसची के अनुसार लिखा व पढा जावे। इस हेतू यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

शपथकर्ता

शपथपत्र

मैं. मो साजिद अंसारी आ० खुशदिल अंसारी उम्र 21 वर्ष निवासी दरीपारा थाना व तह० अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० का निम्नलिखित शपथ पूर्वक कथन करता हूं मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूं मेरे पिता जी का नाम KHUSHDIL ANSARI जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है जो सत्य एवं सही है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12 वीं के अंकसूची प्रमाण पत्र जिसमें मेरे पिता जी का नाम त्रुटिवश MD KHUSHDIL ANSARI अंकित कर दिया गया है जो असत्य है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं के अंकसूची प्रमाण पत्र मे मेरे पिता का नाम सुधार कर MD KHUSHDIL ANSARI के स्थान पर उनका सही नाम KHUSHDIL ANSARI अंकित किया जाये जिस हेतु संशोधित नवीन अंकसूची प्रदाय करने के सम्बध में अपना स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

का शपथ
शपथकर्ता

भारत सरकार के राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जिला सूरजपुर के विकासखण्ड रामानुजनगर, में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत गठित की गई बहु उद्देशीय किसान उत्पादक सहकारी समिति में क्रियान्वयन मार्गदर्शिका की कण्डिका 10.3 के अनुसार लेखापाल की नियुक्ति की जानी है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र	समिति का नाम	कार्यक्षेत्र / विकासखण्ड	लेखापाल की पद संख्या
1	किसान विकास सहकारी समिति मर्यादित पतरापाली, पंजीयन क्रमांक-451	रामानुजनगर	01

लेखापाल हेतुः-

1. गणित / वाणिज्य विषय में हायर सेकण्डरी (10+2) में उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर ज्ञान।
2. कार्यक्षेत्र के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. समिति के कार्यक्षेत्र के सदस्य को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. एकमुश्त 10000.00 रुपए प्रतिमाह।

आवेदन अवधिः-

दिनांक 17/07/2026 से 24/07/2026 तक आवेदन कार्यालय किसान विकास सहकारी समिति मर्यादित पतरापाली, पं.क्र. 451, ग्राम पंचायत पतरापाली, पोस्ट-पतरापाली, विकासखंड-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ०ग०) में जमा कर सकते हैं।

संलग्न दस्तावेजः -

1. आवेदन पत्र।
2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र।

चयन प्रक्रियाः-

1. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षण एवं मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

द्वारा प्राधिकृत अधिकारीः-

किसान विकास सहकारी समिति मर्यादित पतरापाली, पं.क्र. 451 विकासखंड-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर (छ०१०)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

संशोधन पत्र क्रमांक 01

इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सुचना संख्या संख्याः डीआरएम-इंजी-बीएसपी-टी-137-26-27 खुलने की तिथि 28.07.2026, कार्य का नाम "विलासपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोर्हा, रूपौंद, अमलाई, मौहारी और बिजुरी स्टेशनों पर लॉन्ग हॉल लूप लाइनों का निर्माण इसमें मौजूदा तूप लाइनों का विस्तार और नई रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है, साथ ही, लॉन्ग हॉल, फॉर्मेशन/मालगाडी पार्किंग ऑपरेशन के लिए मेन लाइन से कनेक्टिविटी, रास्ते (पाथवे) बनाना और अन्य सबंधित सिविल व पी.वे (P. Way) कार्य, तथा अमलाई स्टेशन पर ट्रैक मशीन साइडिंग का निर्माण कार्य भी शामिल है।" के कार्य के नाम में निम्नवत संशोधन किया जाता है।

विवरण – पहले प्रकाशित निविदा मूल्य : ₹ 42,82,21,585.08/-। संशोधित मूल्य : ₹ 41,94,05,792/-। पहले प्रकाशित अमानत राशि : ₹ 85,64,400/-। संशोधित मूल्य : ₹ 83,88,100.00/-।

निविदा सुचना में उपरोक्त शुद्धिपत्र को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट का पता https://www.ireps.gov.in है।

वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर)
सीपीआर/10/289 द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर

South East Central Railway @secrail

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एवद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स इस्टेट बिल्डकॉन द्वारा डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा आ०स्व० जमुना प्रसाद सिन्हा जाति कायस्थ निवासी मोहल्ला मायापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 15/2 रकबा 0.355 हे0 मेसे 1080 वर्गफीट भूमि एवं उस पर निर्मित मकान को अनावेदक चंदन कुमार आ०अजीत कुमार व अन्य निवासी वार्ड नंबर 12 इमलीपारा भटगांव तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 65,00,000/- मे सौदा तय कर विक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांकः 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स इस्टेट बिल्डकॉन द्वारा डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा आ०स्व० जमुना प्रसाद सिन्हा जाति कायस्थ निवासी मोहल्ला मायापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 15/2 रकबा 0.355 हे0 मेसे 1080 वर्गफीट भूमि एवं उस पर निर्मित मकान को अनावेदक राहुल कुमार पाण्डेय आ०विश्वेश्वर पाण्डेय निवासी वार्ड नंबर-14 भटगांव कॉलोनी सूरजपुर छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 44,00,000/- मे सौदा तय कर विक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांकः 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शारदा अग्रवाल पत्नी ओ०पी० अग्रवाल निवासी बसंतलाल मार्ग अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4557/55 रकबा 0.011 हे0 भूमि एवं उस पर निर्मित मकान को अनावेदक पूजा अग्रवाल पत्नी विश्वास कुमार अग्रवाल निवासी सी0ई0-21 वसुधरा कुण्डला सिटी, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग० के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 48,00,000/- मे सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांकः 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

ईश्तहार एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हरमीत कौर पत्नी मंजीत सिंह छाबडा वअ न्य निवासी कुण्डला सिटी, अग्रसेन वार्ड मकान नंबर बीडब्ल्यू-7 अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग० के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4557/41 रकबा 0.018 हे0 भूमि एवं उस पर निर्मित मकान को अनावेदक सुनील कुमार अग्रवाल आ०स्व० किशोरी लाल अग्रवाल निवासी कुण्डला सिटी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग० के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 60,00,000/- मे सौदा तय कर विक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा भिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। तहसीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांकः 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

तहसीलदार

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ०ग०)

रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जितेन्द्र कुमार जैन आ०स्व० सुभाषचंद्र जैन निवासी खरसिया रोड अम्बिकापुर वर्तमान निवासी टिटलागढ द्वारा मुख्तार खास सरला अग्रवाल पत्नी संजय अग्रवाल पिता स्व० सुभाषचंद्र जैन निवासी अग्रसेन वार्ड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्य एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4402/4 रकबा 0.027 हे0 भूमि को अनावेदक रेसू अग्रवाल पति नवीन अग्रवाल निवासी खरसिया नाका ग्रीन पार्क कॉलोनी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 18,00,000/- मे सौदा तय कर बिक्की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः 14/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)

रा०प्र०क०/ब-121/2025-26

ग्राम - परसवारकला

तहसील राजपुर

ईश्तहार

एत्द द्वारा सर्वसाधारण आम जनता परसवारकला को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बचन राम आ० गवजाति गोड़ निवास ग्राम परसवारकला थाना राजपुर तहसील राजपुर जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अपनी माता स्व. मोतीया पति स्व. गवटियाराम का मृत्यु दिनॉक 13.03.2018 को मृत्यु हुआ है। किन्तु मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वंश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र पेश है। जो न्यायालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 30/07/2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक.06/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुभाष कुमार अग्रवाल आ.स्व. सीताराम अग्रवाल, उम्र 60 वर्ष, जाति अग्रवाल निवासी बंगाली चौक बौरीपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के द्वारा अनावेदिका श्रीमती किरण वर्मा पति स्व. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, उम्र 75 वर्ष के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अं०पुर, शीट नं. 04 मोहल्ला बौरीपारा अ०पुर स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 2038/6 में से रकबा 0.11 एकड़ भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 06.07.2026 के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंयः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 30 /07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।' आज दिनांक- 14/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग०

रा०प्र०क्र०-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण गीता सिंह, अंजनी सिंह, महेश सिंह भगत, गणेश सिंह आ.स्व. गोपाल सिंह, सभी निवासी डी०सी० रोड़, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के पिता स्व. गोपाल सिंह के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, मोहल्ला-महावीर वार्ड स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1893/4777/10 रकबा 0.02 1/4 एकड़ भूमि है। भूधारक गोपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 18/07/2002 को हो गई है। अतः भूधारक की मृत्यु हो जाने उपरांत उक्त आवेदित भूखण्ड से उनका नाम विलोपित कर स्वयं के नाम से आवेदित भूमि का फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा मृत्तक गोपाल सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 31/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपात पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 20/05/ 2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

फिल्म इवेंट

हॉलीवुड

दुआ ने टर्नर के साथ ऑफिशियली अनाउंस की शादी, शेयर की चार खूबसूरत तस्वीरें

ग्लोबल पॉप स्टार दुआ लीपा और एक्टर कैलम टर्नर ने आखिरकार शादी कर ली है। दोनों ने आधिकारिक तौर पर आज सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा की है। दुआ ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की चार खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर यह खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की है।

दुआ लीपा ने एक्टर कैलम टर्नर से शादी कर ली है। जिसकी खास झलक दुआ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरें के साथ दुआ ने अपनी वेडिंग डेट को मेंशन किया है। दुआ ने लिखा, '31.05.2026'

दुआ की इस पोस्ट पर गिगी हदीद ने उन्हें शादी की बधाई दी है। गिगी हदीद ने लिखा, 'बेहद खूबसूरत, बधाई हो।' दुआ की इस पोस्ट पर बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने ब्लैक और लाल दिल वाले इमोजी बनाएं हैं।

अपनी शादी में दुआ लिपा ने डैनियल रोजबेरी द्वारा डिजाइन किया गया खास सूट पहना है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग ग्लव्स, जूते और एक बड़ी सी व्हाईट कैप पहनी हुई है। टर्नर नेवी सूट और टाई में नजर आए और दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे बेहद खुश दिख रहे हैं। दुआ और टर्नर के फैंस उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर शादी की बधाई दे रहे हैं। दोनों कलाकारों का रिश्ता पहली बार जनवरी 2024 में सुर्खियों में आया था। जून 2025 में लीपा ने अपनी सगाई की पुष्टि की थी।

टॉलीवुड

रुक्मिणी के साथ फिल्म बनाने जा रहे नानी, लीड एक्टर की तलाश जारी

साउथ के मशहूर अभिनेता नानी अब रुक्मिणी वसंत के साथ एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म के लिए लीड एक्टर की तलाश जारी है। साउथ के अभिनेता और फिल्ममेकर नानी अपने प्रोडक्शन हाउस 'वॉल पोस्टर सिनेमा' के तहत एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर 'कांतारा चैप्टर 1' की अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत को कास्ट किया गया है। खबरों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को मुरलीकांत देवसोथ डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्ममेकर को पहले अपनी रूरल ड्रामा फिल्म 'धंडोरा' के लिए तारीफ मिल चुकी है।

नानी की टीम अभी स्क्रिप्ट और प्री-प्रोडक्शन के दूसरे कामों पर काम कर रही है। सूत्रों का कहना है कि मुरलीकांत कहानी को फाइनल टच दे रहे हैं और साथ ही सपोर्टिंग कास्ट और टेक्निकल क्रू को भी तय कर रहे हैं। मेकर्स फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले हर पहलू की सावधानी से प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बड़ी अपडेट फीमेल लीड का चुनाव है। खबर है कि हीरोइन के रोल के लिए एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत को चुना गया है। एक्ट्रेस ने फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी है। रुक्मिणी अपनी परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रही हैं।

खबर है कि इस फिल्म के लिए लीड एक्टर की तलाश अभी जारी है। प्रोडक्शन टीम ऐसे सही एक्टर की तलाश में है जो कहानी में फिट बैठे और किरदार में जान डाल सके। हीरो के तय होने के बाद, मेकर्स के इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने की उम्मीद है।

फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होने की संभावना है। तब तक टीम तैयारी जारी रखेगी और जरूरी शुरुआती काम पूरे कर लेगी। चूंकि फिल्म नानी के बैनर तले बन रही है, इसलिए फिल्म प्रेमियों के बीच अभी से उम्मीदें बढ़ रही हैं।

भोजपुरी

'मर्द का प्यार नहीं आदत हो जाती है'-काजल पर बोले खेसारी

खेसारी लाल यादव बोले- पवन सिंह ने कहा था कि खेसारी के साथ कभी काम नहीं करूंगा और उसके बाद से मैं इंडस्ट्री में काम कर ही रहा हूं। उन्होंने काजल राघवानी को लेकर भी बातें की और कहा- मैं तो ये कहूंगा कि मर्द का प्यार नहीं आदत हो जाती है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर पवन सिंह की तरफ निशाना साधा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट पर खेसारी लाल यादव ने काफी सारी बातें की हैं। उन्होंने पवन सिंह पर तीखा वार करते हुए कहा, 'मैं इस इंडस्ट्री में उनके बाद आया लेकिन उनसे अधिक फिल्में की हैं।'

खेसारी लाल यादव पवन को लेकर बोले, 'उन्होंने कहा था कि खेसारी के साथ कभी काम नहीं करूंगा और उसके बाद से मैं इंडस्ट्री में काम कर ही रहा हूं। पवन सिंह के साथ मैंने एक ही फिल्म की है। सच बात सबको अच्छी नहीं लगती। मैं पवन सिंह का चमचा नहीं हूं।'

खेसारी ने काजल राघवानी को लेकर भी बातें की। उन्होंने कहा, 'उस वक्त वो मेरे लिए सही थीं तो आज भी सही हैं। इंसान को प्यार हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि मर्द का प्यार नहीं आदत हो जाती है। जब प्यार हो तो बेबी-सोना, ब्रेकअप के बाद सब गलत बताते हैं।'

एक्टर ने अपने संघर्ष पर भी बातें कीं। उन्होंने कहा, 'हमारे पास जमीन नहीं थी। हमलोग चाचा के साथ गांव में रहते थे। पिताजी दिल्ली में काम करते थे।

लाइफ स्टाइल

सादगी की मिसाल

फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एफडीसीआई) ने 'भारत टेक्स' में उत्साहजनक भागीदारी दी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शानदार ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट में भारत की टेक्सटाइल वैल्यू चेन और टिकाउ फ़ैशन को दिखाया गया। जाने-माने डिज़ाइनरों ने इनोवेशन और कारीगरी के मेल से बनी अपनी सादगी से भरपूर नई क्रिएशन पेश की। इस इवेंट को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इसने फ़ैशन की दुनिया में आए बदलावों को उजागर किया।

क्या आप भी स्किन पर लगाते हैं परफ्यूम तो जानिए इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स

गर्मी का मौसम है। इस मौसम में हर कोई परफ्यूम को अपना दोस्त बना लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मौसम में पसीना काफी ज्यादा आता है, जिस कारण शरीर में से बदबू आने लगती है। ऐसे में परफ्यूम इस बदबू से आपको छुटकारा दिलाता है।

ऐसा माना जाता है कि यदि परफ्यूम को स्किन पर लगाया जाए तो इसकी खुशबू लंबे समय तक टिकती है। इसलिए लोग कलाई या फिर गर्दन पर इसे लगाते हैं। पर, क्या आप जानते हैं कि स्किन पर परफ्यूम लगाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहां हम आपको स्किन पर परफ्यूम लगाने के नुकसान आपको बताने जा रहे हैं।

एलर्जी की संभावना

यदि आप स्किन परफ्यूम लगाते हैं तो उसमें मौजूद केमिकल्स स्किन पर रैश, खुजली, लाल चकत्ते या जलन का कारण बन सकते हैं। कई बार तो सस्ते परफ्यूम की वजह से

दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर तक की सलाह लेनी पड़ सकती है। इसलिए जितना हो सके स्किन पर परफ्यूम लगाने से बचें।

डार्क स्पॉट्स

हम सभी पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही परफ्यूम लगाते हैं। ऐसे में यदि आप स्किन पर परफ्यूम लगाकर तुरंत बाहर जाएंगे तो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है। इसकी वजह से स्किन पर काले धब्बे हो सकते हैं। पिग्मेंटेशन की वजह से आपका लुक भी खराब हो सकता है। इसलिए यदि स्किन पर परफ्यूम अप्लाई कर रहे हैं तो तुरंत बाहर न निकले।

बढ़ेगी त्वचा की ड्राईनेस

अक्सर जब हम स्किन पर परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो अल्कोहल-बेस्ड परफ्यूम स्किन से नैचुरल नमी खींच लेता है। इस कारण त्वचा अपने आप रूखी हो जाती है। इसकी वजह से स्किन तो काफी डल हो जाती है। इसलिए स्किन पर परफ्यूम लगाने से बचें।

स्किन पर होगी इरिटेशन

ज्यादातर लोग गले पर परफ्यूम लगाते हैं या फिर कलाई पर। ऐसे में एक ही जगह पर बार-बार परफ्यूम जगह लगाने से स्किन लाल और सेंसिटिव हो सकती है।

बारिश में रोमांटिक डेट का प्लान है तो पहनें ये

देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की दस्तक बस होने की है। वैसे भी बारिश का मौसम काफी सुहावना होता है। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत बनकर घूमने की प्लानिंग जरूर करें। फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक में बारिश का काफी महत्व होता है। जैसे ही बारिश का ये मौसम शुरू होता है, वैसे ही आस-पास हरियाली दिखने लगती है। मन भी काफी खुशनुमा सा हो जाता है। ऐसे में लोग इस मौसम में अपने अपनों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। यदि आप भी बारिश के मौसम में अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाने वाली हैं तो अपने कपड़ों का खास ध्यान रखें। यहां हम आपको कुछ ऐसे ही आउटफिट्स का कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं, जिसे पहनने के बाद आप बारिश में लगेंगी भी बेहद प्यारी और इन कपड़ों को पहनकर आपका लुक सजह रहेगा।

डेनिम शॉर्ट्स और टॉप

यदि आप कॉटन शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहती हैं तो डेनिम शॉर्ट्स को प्राथमिकता दें। इसके साथ टैंक टॉप पहनकर आप अपने लुक को ग्लैमरस बना सकती हैं। इसके साथ पैरों में साधारण चप्पल पहनने की बजाए जूते कैरी करें। बालों को खुला रखेंगी तो आपका लुक ज्यादा खूबसूरत दिखेगा।

फ्लोरल मिडी

बरिश के मौसम में आस-पास काफी हरियाली होती है। इसलिए ऐसी फ्लोरल मिडी भी आप कैरी कर सकती हैं। मिडी पहन रही हैं तो उसके साथ स्लीपर पहनें। बारिश के मौसम में हील्स आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी ड्रेस के साथ बालों को कर्ल करके खुला रखें। इस खूबसूरत से मौसम में यदि आप ब्लू रंग की बॉडीकॉन ड्रेस पहनेंगी तो आपका पार्टनर आप पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा। ऐसे में अपने लिए एक ऐसी ड्रेस अवश्य खरीद लें। इसके साथ चाहें तो हल्की हील पहनें, क्योंकि ऐसी ड्रेस के साथ हील्स ही अच्छी लगेंगी। साथ ही में अपने बालों को कर्ल करें।

कहीं फेशियल के नाम पर आपके चेहरे से तो नहीं हो रहा खिलवाड़

चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लेकर पुरुष भी फेशियल कराते हैं। यदि इस ट्रीटमेंट के बाद भी चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ रही है तो चेक करें कि आपके साथ भी फेशियल के नाम पर खिलवाड़ नहीं हो रहा है।

चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आज-कल तमाम तरह के स्किन केयर ट्रीटमेंट चलन में हैं। इन्हीं में एक है फेशियल। महिलाओं से लेकर पुरुष तक फेशियल से कराकर अपना चेहरा चमकाते हैं। इसकी वजह से चेहरे की डीप क्लींजिंग हो जाती है। ये त्वचा को निखारने और ताजगी देने का एक लोकप्रिय तरीका है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से न किया जाए, तो यह आपकी त्वचा के लिए हानिकारक भी हो सकता है।

अक्सर पार्लर में जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिस कारण चेहरा दमकने के जगह मुरझा जाता है। यहां हम आपको इन्हीं गलतियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, ताकि आप भी फेशियल कराते समय ध्यान रखें।

त्वचा में जलन

यदि फेशियल के दौरान आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुजली या जलन हो रही है तो इसे इग्नोर न करें। क्योंकि कई बार केमिकल युक्त क्रीमें त्वचा को सूट नहीं करती हैं। ऐसे में खुजली और जलन आपको परेशान कर सकती है। कई बार तो ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि आपका चेहरा तक बिगड़ सकता है। इसलिए यदि कोई क्रीम रिएक्ट कर रही है तो उसे तुरंत हटवा दें। फेशियल के दौरान चेहरे पर मसाज की जाती है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो आपके चेहरे पर इस मसाज से चेहरा लाल हो सकता है।

ये एक फूल देगा आपके बालों को नया जीवन, कीजिए इसका सही इस्तेमाल

प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल का असर अब लोगों की सेहत के साथ-साथ उनके बालों और त्वचा पर पड़ने लगा है। हम सभी चेहरे का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन अक्सर बालों की देखभाल करना भूल जाते हैं। ऐसे में आपको एक ऐसे फूल के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसका हेयर मास्क बनाकर आप बालों से संबंधित कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं।

यहां बात है गुड़हल के फूल की। इस में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण कहा जा सकता है कि ये फूल बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए आपको भी इसके इस्तेमाल का तरीका और फायदे बताते हैं।

गुड़हल हेयर मास्क

इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें पहला तो गुड़हल का फूल है, और दूसरा है दही या फिर एलोवेरा जेल। यदि आपका स्कैल्प ड्राई है तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। ऑयली स्कैल्प वाले लोग दही का इस्तेमाल करें।

मास्क बनाने की विधि

अब बारी आती है इस हेयर मास्क को तैयार करने की। हेयर मास्क तैयार करने के लिए सबसे पहले गुड़हल के फूल को अच्छे से धोकर उसे ब्लैंडर में डालें और पीस लें। इसका आपको एकदम महीन पेस्ट बना लेना है। फूल को पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दही या फिर एलोवेरा जेल अपनी जरूरत के हिसाब से डालें और मिक्स करें। अब ये पेस्ट तैयार है। इसका इस्तेमाल काफी आसान है। इस्तेमाल के लिए सबसे पहले अपने बालों को खोलकर सुलझा लें।

कार्नर न्यूज

बदलते दौर में चलन बड़ रहा लिप सर्जरी का

खूबसूरत दिखने अब लोग सहारा ले रहे लिप सर्जरी का, जानें इसका तरीका और संभावित नुकसान

जैसे-जैसे समय बदल रहा है, वैसे-वैसे लोगों के रहन-सहन से लेकर पहनावे में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक समय था, जब खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं सिर्फ मेकअप का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन आज के समय महिलाएं तरह-तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले रही हैं। इन्हीं ट्रीटमेंट में शामिल है लिप सर्जरी।

जी हां, होंठों का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए अब महिलाएं लिप सर्जरी कराना पसंद करती हैं। इससे लुक में काफी बदलाव देखने को मिलता है। कई अभिनेत्रियां नियमित रूप से लिप सर्जरी कराकर अपने लुक को खूबसूरत बनाती हैं। ज्यादातर महिलाओं को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, कि ये लिप सर्जरी कैसे होती है और इसके नुकसान क्या हैं। इसी के चलते हम आपको यहां इस सर्जरी से जुड़ी हर बात बताएंगे। ये सर्जरी मुख्यत दो प्रकार से की जाती है, आइए जानते हैं इसके बारे में।

लिप ऑग्मेंटेशन

जो महिलाएं अपने होंठों का आकार

बढ़ाना चाहती हैं, यानी कि होंठों में उभार चाहती हैं वो लिप ऑग्मेंटेशन कराती हैं। ज्यादातर अभिनेत्रियां इस सर्जरी को कराकर अपने होंठों के आकार में बदलाव करती हैं। इस आसान की सर्जरी में हायालूरोनिक एसिड जैसे फिलर होंठों में इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किए जाते हैं।

इस प्रक्रिया को पूरा होने में तरकीबन आधे घंटे का समय लगता है। इसे एक बार कराने के बाद इसका असर तकरीबन 8 महीने से एक साल तक तो रहता ही है। जो महिलाएं स्थायी रूप से अपने होंठों को मोटा बनाना चाहती हैं, वो डॉक्टर की सलाह पर सिलिकॉन का इस्तेमाल भी कराती हैं।

इसके नुकसान

कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि लिप ऑग्मेंटेशन के बाद होंठों पर जलन, लालिमा और दर्द का एहसास होता है। कई मामलों में तो दिक्कत तब सामने आती है जब फिलर की वजह से होंठों का आकार ही बदल गया हो। इसकी वजह से होंठ टेढ़े-मेढ़े दिखने लगते हैं। एलर्जी की थोड़ी सी भी संभावना लग रही तो इसे इग्नोर न करें, बल्कि तत्काल ही डॉक्टर की सलाह लें।

लिप रिडक्शन

इसके नाम से ही आपको क्लीयर हो गया होगा कि इसका काम होंठों का आकार पतला करना है। जिन महिलाओं के होंठ काफी ज्यादा मोटे होते हैं, वो इस सर्जरी के माध्यम से अपने होंठों को पतला कराती हैं। ये भी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। जिसमें होंठ के अंदर से अतिरिक्त ऊतक को हटाया जाता है और टांके लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए व्यक्ति को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

इसके नुकसान

लिप रिडक्शन सर्जरी के मामले में कई बार घाव ठीक होने में काफी समय लगता है। यदि इसे सही जगह से न कराया जाए तो टांकों के निशान रह जाते हैं, जो देखने में अजीब लगते हैं। इससे कई बार बोलने में भी दिक्कत होती है।

इन बातों का ध्यान रखकर कराएं सर्जरी

यदि आपका लिप सर्जरी कराने का मन है तो सबसे पहले तो एक अच्छे कॉस्मेटिक डॉक्टर की सलाह लें। वहां जाकर अपना टेस्ट कराएं कि आपकी स्किन सर्जरी के लिए सही है या नहीं।

भाजयुमो के शुभम सरगुजा संभाग प्रभारी और कोमल सूरजपुर जिला प्रभारी नियुक्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। भाजयुमो प्रदेश नेतृत्व द्वारा संगठन की मजबूती के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। इन नई नियुक्तियों में शुभम जायसवाल को सरगुजा संभाग का संगठन प्रभारी एवं लोकेश साहू को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं, भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल पटेल को जिले का संगठन प्रभारी तथा आनंद ताम्रकार को सहप्रभारी घोषित किया गया है। ?इन संगठनात्मक नियुक्तियों से जिले सहित सरगुजा संभाग के भाजयुमो कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने नवनियुक्त संभाग प्रभारी शुभम जायसवाल, संभाग सहप्रभारी लोकेश साहू, तथा सूरजपुर जिला प्रभारी कोमल पटेल एवं जिला सहप्रभारी आनंद ताम्रकार को शुभकामनाएं प्रेषित कीं। देव गुप्ता ने कहा, सभी के कुशल नेतृत्व, ऊर्जावान मार्गदर्शन और संगठनात्मक अनुभव से सरगुजा संभाग और विशेषकर सूरजपुर जिले में पार्टी को एक नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी और जिले में युवा मोर्चा और अधिक सक्रियता से कार्य करेगा तथा संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता : रेना जमील

शिक्षा से समन्धित विभिन्न योजनाओं की कलेक्टर ने की समीक्षा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में शाला प्रवेशोत्सव, शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों एवं छात्रावासों की व्यवस्थाओं तथा आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने विस्तृत समीक्षा करते हुएअधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की वीएसके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति तथा विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों की नियमित ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन विद्यालयों में वीएसके ऐप में तकनीकी समस्या आ रही है, वहां पुन: लोकेशन मैपिंग कर समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं प्रोग्रामरों को दिए।

संकुल समन्वयकों को भी शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा शिक्षकों को शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करने को कहा। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने, बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों द्वारा अभिभावकों की काउंसलिंग करने तथा विद्यालयों में न्योता भोज का नियमित आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें पुन: विद्यालय से जोड़ने, बच्चों की बेसिक नॉलेज मजबूत करने, स्कूलों के क्लस्टर बनाकर शैक्षणिक एवं खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा नवाचारों के माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। साथ ही विद्यालयों की छोटी-बड़ी सभी समस्याओं की जानकारी तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विद्यालय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नवीन भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा करने तथा मरम्मत योग्य भवनों का प्राथमिकता के आधार पर सुधार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकतानुसार नए भवनों की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। विद्यालयों एवं छात्रावासों में शौचालयों की उपलब्धता, उनकी साफ-सफाई एवं उपयोगिता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जहां शौचालय नहीं हैं या पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाए। जिन विद्यालयों में शौचालय उपयोग योग्य नहीं पाए जाएंगे, वहां संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। स्वच्छता एवं शौचालय उपयोग के प्रति सिविक सेंस विकसित करने के लिए भी शिक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। विद्यालयों या छात्रावासों में पेयजल, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां सोलर आधारित बिजली व्यवस्था स्थापित है, वहां किसी भी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल सूचना देकर मरम्मत कराई जाए।

जिन विद्यालयों में बिजली व्यवस्था उपलब्ध नहीं है या बाधित है, वहां की रिपोर्ट तैयार कर क्रेडा विभाग के समन्वय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बीईओ एवं बीआरसी को नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने देवगुड़ी निर्माण, छात्रावासों में आवश्यक सुविधाओं, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति तथा छात्रावासों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रावासों में किचन, बेड, दरवाजे, खिड़कियां एवं भवनों की स्थिति बेहतर रखी जाए तथा पानी के रिसाव जैसी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। वर्षा ऋतु को देखते हुए छात्रावासों एवं विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जर्जर भवनों का उपयोग पूरी तरह बंद रखने तथा बच्चों की सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने छात्रावासों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को जागरूक करने, अधीक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों एवं छात्रावास अधीक्षकों द्वारा शैक्षणिक दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही अथवा शराब सेवन की शिकायत मिलने पर तत्काल कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विद्यालयों एवं छात्रावासों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधनों की जानकारी लेकर सुविधाएं विकसित करने को कहा।

बैठक में उल्लास कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।

जिले में प्रारम्भ हुआ तीन दिवसीय शिविर, सरकारी सेवाओं को एक मंच पर लाने की पहल

पहले ही दिन 4793 लोगो ने उठाया लाभ

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम छोर तक के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देश पर जिलेभर में 16 से 18 जुलाई तक तीन दिवसीय वृहद शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, आधार कार्ड, एग्री स्टेक किसान पंजीयन, श्रमिक केवाईसी तथा विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी सहित विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभियान के प्रथम दिवस जिले के सभी विकासखंडों में निर्धारित स्थलों पर संबंधित विभागों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से शिविर आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समन्वित रूप से

उपस्थित होकर हितग्राहियों का पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कराते हुए सेवाएं उपलब्ध कराईं। शिविरों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दिवस 21 सौ आयुष्मान कार्ड, 339 आयुष्मान वय वंदन कार्ड तथा 21 सौ आभा आईडी कार्ड बनाए गए। इसके अतिरिक्त 254 हितग्राहियों का आधार नामांकन भी किया गया। अन्य विभागों द्वारा भी एग्रीस्टेक किसान पंजीयन, श्रमिक केवाईसी एवं अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी रही।

कलेक्टर ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 18 जुलाई तक अपने निकटतम शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक हितग्राही को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की जनहितकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश, बोलीं- सीएसआर मद के कार्यों को दें गति

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने वन, खनिज, उद्योग, श्रम, एसईसीएल एवं पर्यावरण विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्थानीय स्तर पर छोटे उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा स्किल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध संसाधनों एवं स्थानीय युवाओं के कौशल का बेहतर उपयोग कर रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जाएं, ताकि युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध हो सके। जिले में अवैध उत्खनन एवं अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने खनिज विभाग को निर्देश दिए। कलेक्टर ने वन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित पौधरोपण अभियान एवं पौधों के संरक्षण की वन विभाग से जानकारी ली। उन्होंने अधिक से अधिक पौधरोपण के साथ लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं जीवितता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की योजनाओं एवं प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा विभागीय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन पर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसईसीएल द्वारा जिले में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्वीकृत एवं संचालित विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने एसईसीएल के अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समय-सीमा में शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि जिले के नागरिकों को इन परियोजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। इसके अलावा प्रकाश इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप द्वारा भी सीएसआर के तहत स्वीकृत कार्यों और उसके प्रगति की जानकारी साझा की गई।

गाँवों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने निभाएं सक्रिय भागीदारी : पाटले

जिपं सीईओ ने किया रामानुजनगर क्षेत्र के पंचायतों का निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिपं सीईओ विजेन्द्र सिंह पटले द्वारा जनपद रामानुजनगर के ग्राम मदनेश्वरपुर, तेलईमुड़ा एवं पास्ता में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की क्रियाशीलता एवं गुणवत्ता का जायजा लेते हुए हितग्राहियों से संवाद किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत मदनेश्वरपुर में निर्मित बायोगैस संयंत्र का अवलोकन किया गया तथा हितग्राहियों से चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने सचिव एवं माध्यमिक शाला के प्राचार्य को मध्याह्न भोजन पकाने हेतु बायोगैस का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि स्वच्छ ऊर्जा को व्यावहारिक धरातल पर उपयोग में लाया जा सके। तेलईमुड़ा में बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण कर उसे निरंतर क्रियाशील बनाए रखने के संबंध में हितग्राहियों से चर्चा की गई। इस दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप प्रत्येक घर में गीले एवं सूखे कचरे को पृथक पृथक रखने तथा उसे स्वच्छाग्राहियों को सौंपे जाने के संबंध में जागरूकता लाने पर बल दिया गया। इसके उपरांत ग्राम पास्ता में बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण किया गया, जहाँ कुछ हितग्राहियों के कनेक्शन पाइप क्षतिग्रस्त पाए जाने पर उन्हें शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश देते हुए आंगनबाड़ी के बच्चों, सहायिका, पोषण आहार, पोषण ट्रैकर एवं साफ-सफाई की व्यवस्था पर चर्चा की गई तथा बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। रीपा परिसर में संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के निरीक्षण के दौरान संलग्न स्वच्छाग्राही से प्लास्टिक श्रेडिंग, अन्य लिंक ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने वाले कचरे एवं उसके निपटान के संबंध में विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के अंत में निर्माणाधीन फीकल स्लज प्रबंधन इकाई का अवलोकन कर कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा एवं पोषण से जुड़ी ये इकाइयाँ ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ग्रामीणों से समन्वय के साथ कार्य करते हुए इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने तथा गाँवों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

चट्टीडांड़ स्कूल में सम्पन्न हुआ बाल सभा मंत्रिपरिषद चुनाव, बच्चो में दिखा उत्साह, आकर्षित रही मतगणना प्रक्रिया

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुभवात्मक एवं सहभागितापूर्ण शिक्षण को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में शासकीय प्राथमिक शाला चट्टीडांड़ ने एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधान पाठक एवं निर्वाचन प्राधिकारी गौतम शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित बाल सभा मंत्रिपरिषद निर्वाचन - 2026 के अंतर्गत बुधवार को मतदान एवं मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की तर्ज पर सम्पन्न हुई। विद्यालय परिसर पूरे दिन लोकतंत्र के वास्तविक उत्सव में परिवर्तित रहा, जहाँ नन्हें मतदाताओं ने उत्साह और अनुशासन के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

इस निर्वाचन की विशेषता यह रही कि अन्य विद्यालय से नियुक्त प्रशिक्षित छात्र मतदान दल ने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किया। परी सारथी ने पीठासीन अधिकारी तथा दिव्या सारथी, अल्का सारथी एवं आराधना सारथी ने मतदान अधिकारियों के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। निर्वाचन में सातों मंत्री पदों के लिए अलग-अलग रंगों के मतपत्र विशेष आकर्षण रहे, जिससे मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, सरल और त्रुटिरहित बनी।

निर्वाचन को वास्तविक स्वरूप देने के लिए पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर, निर्वाचक नामावली, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र, मतदाता पर्ची, मतपत्र लेखा, गणना पर्ची, मतगणना प्रपत्र, मतपेटी तथा अमिट स्याही सहित निर्वाचन आयोग में प्रयुक्त प्रमुख व्यवस्थाओं का उपयोग किया गया। बीएलओ द्वारा मतदाताओं का सत्यापन कर कतारबद्ध मतदान कराया गया तथा मतदान उपरांत अमिट स्याही का निशान लगाया गया। बाद में मतपत्र लेखा, गणना पर्ची एवं मतगणना प्रपत्र के मिलान के साथ पारदर्शी ढंग से मतगणना सम्पन्न की गई।

कार्यक्रम का अवलोकन करने पहुँचे जिला मिशन समन्वयक मनोज कुमार साहू, विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक मनोज मंडल, विकासखण्ड स्रोत केन्द्र समन्वयक भैयाथान सुरेन्द्र दुबे, विकासखण्ड परियोजना अधिकारी जयराम प्रसाद तथा शिक्षक राधेश्याम साहू ने निर्वाचन आयोग की तर्ज पर विकसित व्यवस्थाओं एवं प्रधान पाठक गौतम शर्मा की नवाचारी पहल की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 के अनुभवात्मक अधिगम का उत्कृष्ट मॉडल बताया।

प्रधान पाठक एवं निर्वाचन प्राधिकारी गौतम शर्मा ने बताया कि निर्वाचन परिणामों की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी तथा विजयी अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान कर नवगठित बाल सभा मंत्रिपरिषद का विधिवत गठन किया जाएगा। इस पूरे आयोजन में शिक्षिका श्रीमती मंजू कुजूर, शिक्षक लौकेश कुमार साहू, शाला प्रबंधन समिति की अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रलेखा, उपाध्यक्ष सरीफन सारथी, सदस्य सुमित सारथी एवं भूतपूर्व छात्रा भूमि का उल्लेखनीय योगदान रहा।

सुब्रतो मुखर्जी कप अंडर-17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में सूरजपुर की बेटियों का शानदार प्रदर्शन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सुब्रतो मुखर्जी कप अंडर-17 वर्ष बालिका शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिले की बेटियों ने खेल के मैदान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का मान बढ़ाया है। इस प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर-17 बालिका वर्ग में सूरजपुर की टीम ने दोहरे पदक अपने नाम कर एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फुटबॉल टूर्नामेंट में कड़े मुकाबले के बीच सूरजपुर की बालिकाओं ने संभाग स्तर पर अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। संभाग स्तर पर मिली इस शानदार जीत के पश्चात टीम का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ, जहाँ बालिकाओं ने अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाया। राज्य स्तर पर आयोजित स्पर्धाओं में भी सूरजपुर की बालिकाओं का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। फाइनल के रोमांचक मुकाबले में टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए उपविजेता रही और रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती लता बैक, सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी शरदेन्दु कुमार शुक्ल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर प्रताप सिंह पैकरा, कोच रावेन्द्र वर्मा एवं टीम मैनेजर विमल डुंगडुंग ने बालिकाओं के समर्पण, परिश्रम एवं अनुशासन की सराहना की।

जिले के लिए गर्व का विषय- कलेक्टर

विजयी टीम की खिलाड़ियों ने कलेक्टर श्रीमती रेना जमील से मुलाकात की। कलेक्टर ने बालिकाओं को उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं दोहरी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने बालिकाओं के समर्पण, परिश्रम एवं खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि जिले की बेटियों की यह उपलब्धि समस्त जिलेवासियों के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं को निरंतर परिश्रम एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए भविष्य में जिले एवं प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-3966/NIT-04/2026-27/व.ले.लि. दिनांक : 14.07.2026

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 05.08.2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 11.08.2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 13.08.2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
निविदाकारों की श्रेणी :- एकल पंजीयन में पंजीकृत "द" वर्ग ठेकेदार
भवन एसओआर :- 01.01.2015 लागू दिनांक 05.05.2025 तक संशोधित

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्यों की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रू.में) बैंक साल्वेंसी (रू.में) निविदा प्रपत्र की कीमत (रू.में) कार्य की अवधि
4 T0039	जिला सरगुजा के अम्बिकापुर स्थित पशु चिकित्सालय भवन में एवं रोग अन्वेषण प्रयोगशाला का मरम्मत।	6.14 4605.00 100000.00 750.00 03 माह वर्षाऋतु सहित
4 T0039	जिला सरगुजा के अम्बिकापुर स्थित उपसंचालक कार्यालय अम्बिकापुर का मरम्मत।	7.55 5663.00 115000.00 750.00 03 माह वर्षाऋतु सहित

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। एवं निविदा संबंधित शर्तों का अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग अम्बिकापुर

जी-262702116/2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव तहसील भटगांव
रा0प्र0क्र0 /अ-02/2020-21

ईश्तहार

आम जनता ग्राम सलका को सूचित किया जाता है कि आवेदक चमरू आ०स्व० बोधी जाती रजवार निवासी ग्राम सलका तहसील भटगांव जिला सूरजपुर द्वारा अपने माता जुकमनिया का मृत्यु दिनांक 03/11/1978 को मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने पुत्र माता का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवे. दन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 20/07/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। आज दिनांक 06/07/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुदा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव तहसील भटगांव

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका नीलम सेठी आ०/पति अनिल सेठी जाति निवासी अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1951/4 रकबा 0.20 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 20/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 06/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

भगवान राम की आस्था पर डाका डालने वालों को बेनकाब किया जाए

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार, भाजपा, आरएसएस पर सीधे हमला बोला

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने गुरूवार को राजीव भवन में पत्रकारों के समक्ष केंद्र सरकार और भाजपा, आरएसएस पर सीधा हमला बोला। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि, भगवान श्री राम के नाम पर जुटाया गया चंदा और चढ़ावा अब राजनीतिक लूट का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा राम मंदिर निर्माण के लिए रामशिला पूजन के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि देशभर से एकत्र की गई। इसमें गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं ने अपनी मेहनत की कमाई और गहने दान किए। इधर घोटाला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे शीर्ष पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, जो मामले को गंभीर बनाता है। इनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। यह सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया घोर विश्वासघात है।

टीएस सिंहदेव ने खर्चों पर उठे सवाल के प्ररिपेक्ष्य में दो बड़े आयोजनों के खर्च का जिक्र करते हुये कहा कि, 22 जनवरी 2024 की प्राण-प्रतिष्ठा पर लगभग 113 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें 8,000 अतिथि शामिल हुए। 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण कार्यक्रम पर लगभग 10.12 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके अलावा फर्जी रसीदों, नकद चढ़ावा, लेखा-जोखा और हेराफेरी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि एसआईटी अब

इन बड़े आयोजनों के खर्चों की जांच कर रही है, लेकिन सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है। शीर्ष पदाधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई है। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था पर डाका डालने वालों को बचाने की बातें सामने आ रही है, जबकि इन्हें बेनकाब करने की जरूरत है। उन्होंने कहा भगवान श्री राम के नाम पर धार्मिक भाव और धार्मिकता की तिलांजलि दी जा रही है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामने आने के बाद 2 करोड़ की जमीन को साढ़े 18 करोड़ में खरीदना और ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी का जवाब कि, जमीन का भाव तेजी से बढ़ रहा है, हास्यास्पद है। सिंहदेव ने कहा कि राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के समय प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आरएसएस प्रमुख के साथ 5 लोग मंच पर दिखे। इनके द्वारा देश के आस्थावान लोगों की धज्जी उड़ा दी गई। 70 बार रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद भी जिम्मेदारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी चुप्पी साधे रहे। देश के प्रमुख शंकराचार्यों ने कहा कि मंदिर मूर्ति स्थापना और प्राणप्रतिष्ठा के लिये तैयार नहीं है, लेकिन ये 110 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके मीडिया इवेंट देश के सामने प्रस्तुत करते रहे। इस मौके पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, हेमंत सिन्हा, इंद्रजीत सिंह धंजल, हेमंत तिवारी, मो. इस्लाम, दुर्गेश गुप्ता, सीमा सोनी, मदन जायसवाल, अशफाक अली, सतीश बारी सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

एसआईटी का गठन बड़े मामलों को दबाने के लिए

कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि, एसआईटी का गठन बड़े मामलों को दबाने के लिये किया गया है, यह स्पष्ट हो गया है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिये। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री द्वितेन्द्र मिश्रा ने भी पत्रकारों के समक्ष श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और इनके पदाधिकारियों के इस्तीफा को निशाने पर लेते हुये अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से डर क्यों..?-टीएस सिंहदेव ने कहा, ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो घोटाले की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सब ठीक था तो इस्तीफे क्यों हुए? अगर कुछ गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से डर क्यों? इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधते हुये सिंहदेव ने कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश और केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस की मांग है कि, प्रधानमंत्री को ट्रस्ट गठन और पीएमओ की भूमिका को स्पष्ट करके चंपत राय, अनिल मिश्रा और अन्य पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। ट्रस्ट भंग हो, और धर्माचार्यों और विशेषज्ञों वाला नया पारदर्शी ट्रस्ट बने। चंदा, चढ़ावा, भूमि खरीद का ऑडिट सार्वजनिक किया जाए।

आरएसएस है व्यक्तियों का समूह-टीएस सिंहदेव ने कहा कि, आरएसएस कोई संगठन नहीं, व्यक्तियों का समूह है। श्री राम मंदिर न्यास में धार्मिक स्थल की देखरेख और प्रबंधन के लिये देश की सनातनी व्यवस्था को छोड़कर संगठन विशेष के लोगों को जोड़ा गया। पूर्व में आरएसएस का समाज सेवा का स्वरूप था, जो आपदा-विपदा में नजर आते थे। आरएसएस के कर्ताधर्ता अब अनुशांगिक संगठन बनकर भाजपा से जुड़ गए। उन्होंने कहा कि, आरएसएस का आज खुलेआम राजनीति में दखल है। भाजपा के मंत्री और आईएएस अधिकारी तक यहां समीक्षा के लिये जाते हैं।

महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा आस्था और उल्लास के साथ निकली

भक्तों में रथ खींचने के लिये मची होड़, महाप्रभु पहुंचे मौसी के घर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर गुरूवार को शहर में महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथयात्रा निकाली गई, और भगवान देर शाम देवीगंज रोड स्थित मौसी के घर पहुंचे। केदारपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा में हजारों श्रद्धालु उत्साह पूर्वक शामिल हुए।

विदित हो कि, भगवान जगन्नाथ बीमारी से ठीक होने के बाद अपने भाई व बहन के साथ अपनी मौसी के घर 9 दिनों के लिए रहने के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी केदारपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। उत्कल समाज व श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों व अन्य सदस्यों द्वारा रथयात्रा को भव्य रूप प्रदान करने के लिए शैला नर्तक दलों को भी बुलाया

था, मंदिर में सजावट कराई गई थी। इस दौरान मोहल्ले वासियों व नगर के लोगों ने भी जगन्नाथ महाप्रभु के अन्य भक्तों ने यथासंभव सहयोग दिया।

भगवान जगन्नाथ सहित उनके भाई-बहन को रथ में बैठाकर अन्य अनुष्ठानों को पूरा करके भक्तों ने रथ खींचना प्रारंभ किया, इसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ की रस्सी को पकड़ने के लिए लोगों में होड़ मची रही। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर जोड़ा पीपल मार्ग से चौपाटी के पास पहुंचकर पुराने जगन्नाथ मंदिर के पास कुछ समय के लिए रूकी थी, यहां से रथ को आकाशवाणी चौक, गांधी चौक, घड़ी चौक, संगम चौक, ब्रह्म रोड होते हुए श्री राम मंदिर ले जाया गया यहां पर आधे घंटे विश्राम के बाद रथ को जयस्तंभ चौक, महामाया चौक, संगम चौक होते हुए देवीगंज मार्ग से सरस्वती शिशु मंदिर के पास स्थित दुर्गा बाड़ी तक लाया गया, यहां महाप्रभु जगन्नाथ सहित उनके भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा की मूर्तियों को उतारा गया।

विधि-विधान से हुई छेरापहरा पूजा

रथयात्रा निकलने के पहले मंदिर में विधि-विधान से छेरापहरा की पूजा की गई, जिसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद परीड़ा व उनकी पत्नी डॉ. भावना परीड़ा ने जजमान बनकर हर वर्ष की भांति संपन्न कराया। इसके उपरांत बाहुगुड़ी रथ पूजा की गई, तदोपरांत मंदिर परिसर को प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ण झाड़ू से साफ करके भगवान की मूर्तियों को बाहर लाया गया। इस दौरान महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भारी संख्या में मंदिर के भीतर व पूरे परिसर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी।

नौ दिनों तक भगवान रहेंगे मौसी के घर

अगले 9 दिनों तक भगवान मौसी के घर पर ही रहेंगें। इस दौरान पूजा कराने के लिए उड़ीसा से आए पंडित शंभुनाथ पंडा वहीं उनकी सेवा व पूजा करेंगे। इन नौ दिनों तक दुर्गा बाड़ी में प्रतिदिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के पट बंद रहेंगे। नवें दिन भगवान जगन्नाथ अपने घर वापस आने के लिए निकलेंगे तब पुन: रथ पर बैठाकर भगवान व उनके भाई-बहन को गांधी चौक, रिंगरोड से मिशन चौक होते हुए वापस मंदिर लाया जाएगा।

कलेक्टर ने लाईवलीहुड कॉलेज का किया औचक निरीक्षण

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने गुरुवार को शहर के जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान उन्होंने महाविद्यालय में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पंजीकृत प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं (लैब्स), सेमीनार हॉल, संगीत महाविद्यालय सहित अन्य उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने आगामी पटवारी प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कक्षों में पर्याप्त बैठक व्यवस्था एवं सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाईवलीहुड कॉलेज तक आवागमन को सुगम बनाने के लिए रिंग रोड से महाविद्यालय परिसर तक डामर सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने महाविद्यालय भवन का अवलोकन करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सीपेज ठीक कराने कहा, वहीं संगीत महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाईवलीहुड कॉलेज में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास मद से भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने और महाविद्यालय के सेमीनार हॉल के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने कहा।

उन्होंने रिटेल सेल्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हितग्राहियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों का चयन कर प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), जिला प्रशासन द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास मद से अतिरिक्त कम्प्यूटर सिस्टम क्रय करने हेतु आवश्यक राशि की मांग का प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पेसा एक्ट की अनदेखी करके बिना ग्राम सभा सहमति के एसईसीएल डाक से भेजा नोटिस

कटकोना गांव में आक्रोश, 143 परिवारों की जमीन अधिग्रहण पर रोकने की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। एसईसीएल की अमेरा परियोजना द्वारा सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत कटकोना में बिना ग्राम सभा की अनुमति के 143 भूमि स्वामियों को मुआवजा नोटिस भेजे जाने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को पुन: आवेदन सौंपते हुए अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने और आरटीआई के तहत दस्तावेज उपलब्ध कराने कहा है। इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामला एसईसीएल को भेजा जा चुका है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ग्रामवासियों के अनुसार एसईसीएल द्वारा 30.05.2026 को पोस्टमैन के जरिए ग्राम पंचायत कटकोना के 143 भूमि स्वामियों को भूमि के एवज में मुआवजा संबंधी नोटिस भेजा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में ग्राम सभा में आज तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, न ही किसी को जानकारी दी गई। इसे लेकर ग्रामीणों ने 23.06.2026 को जिला कलेक्टर से मुलाकात करके लिखित आवेदन दिया था। कलेक्टर ने इन्हें 15 दिन के बाद आने को कहा था। 14.07.2026 को पुन: कलेक्टर से मिले, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को बताया गया कि आवेदन एसईसीएल को भेज दिया गया है। इसके बाद आयुक्त सरगुजा संभाग के संज्ञान में भी मामले को लाया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा-आपका गांव हुआ अधिग्रहित

ग्रामीणों का कहना है कि, 15.07.2026 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की टीम कटकोना पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि आपका गांव अधिग्रहित हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया होगी। इस पर ग्रामीणों ने जवाब दिया कि यदि 2001 में अधिग्रहण हुआ था तो उसका ग्राम सभा प्रस्ताव

सहित सभी कानूनी दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए। ग्रामीणों ने ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 8 जून 2026 को मान्य कर 143 भूमि स्वामियों की अधिग्रहण कार्रवाई को तत्काल निरस्त करने कहा है, और बिना ग्राम सभा की लिखित सहमति के गांव में प्रवेश, सर्वेक्षण या अधिग्रहण नहीं करने की मांग की है। इनके द्वारा ग्रामीणों को डराने-धमकाने वाले एसईसीएल के अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है।

पूर्व सरपंचों ने सहमति देने से किया इन्कार

2001 से 2025 तक पदस्थ रहे सभी पूर्व सरपंचों सत्यवती सिंह पैकरा, सुमित सिंह मरकाम, तारा सिंह पैकरा, दिनेश सिंह पैकरा, विमला सिंह मरकाम ने कहा कि उनके कार्यकाल में एसईसीएल के संबंध में न कोई एनओसी दिया गया है और न ही सीबीए एक्ट की कोई अधिसूचना मिली है। वर्तमान सरपंच पुष्पा सिंह पैकरा और उपसरपंच शिवकुमारी राजवाड़े ने कहा ग्रामीणों ने आज जमीन दे दी तो आने वाली पीढ़ी बेघर और लाचार हो जाएगी। जमीन कम है फिर भी हमारा जीवन चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता 'बलदेव प्रसाद' ने कहा कि भारत सरकार ने पेसा 1996 लागू किया है और छ.ग. राजस्व परिपत्र 31.01.2000 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से पहले 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदिवासी क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की मंजूरी कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, स्पष्ट किया है।

अंबिकापुर-रायपुर के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रियों को मिलेगी राहत

जेडआरसीसीयू सदस्य ने रेलवे के जीएम को भेजा पत्र

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर से प्रदेश की राजधानी रायपुर के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रारंभ करने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र प्रेषित कर, इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई है। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने महाप्रबंधक, बिलासपुर को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित कर अंबिकापुर और रायपुर के बीच प्रतिदिन सुबह एक सीधी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने की मांग की है, जो कम समय में सीधे रायपुर पहुंच सकेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है,लेकिन सुविधाजनक समय पर सीधी इंटरसिटी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि, अंबिकापुर संभाग मुख्यालय होने के साथ-साथ सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर जिलों के लाखों नागरिकों का प्रमुख रेल केंद्र है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी, मरीज, व्यापारी, अधिवक्ता, शासकीय कर्मचारी एवं आम नागरिक बिलासपुर व राजधानी रायपुर की यात्रा करते हैं। वर्तमान रेल सेवाएं यात्रियों की बढ़ती मांग और समयानुकूल आवश्यकता को पूरा करने में अपर्याप्त हैं। रात्रिकालीन अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस में भी पर्याप्त आरक्षण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

जेडआरयूसीसी सदस्य मुकेश तिवारी ने सुझाव दिया है कि, अंबिकापुर से प्रात: 4 बजे रवाना होकर लगभग 11 बजे रायपुर पहुंचने वाली तथा रायपुर से सायं 4 बजे रवाना होकर रात्रि 11 बजे अंबिकापुर पहुंचने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाए, इससे यात्रियों को एक ही दिन में आवागमन की सुविधा मिलेगी। पत्र में उल्लेख किया गया है कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म एवं पिट लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो आगामी कुछ महीनो में संपन्न होने वाला है। इसके बाद नई ट्रेन का संचालन तकनीकी एवं परिचालन दृष्टि से पूरी तरह व्यवहारिक होगा। इस प्रस्ताव पर 26 मई 2025 की 20वीं जेडआरयूसीसी की बैठक में विचार करने तथा 23 फरवरी 2026 की 21वीं जेडआरयूसीसी बैठक में संज्ञान लेकर अग्रेतर कारवाई के लिए आश्वासन दिया गया था। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से उत्तर छत्तीसगढ़ और प्रदेश की राजधानी रायपुर के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, रेलवे की आय बढ़ेगी तथा क्षेत्र के लोगों को किफायती एवं सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध होगा। उन्होंने महाप्रबंधक से आग्रह किया है कि, जनभावनाओं, बढ़ती यात्री मांग और तैयार हो रही आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत किया जाए।

चोरी के तिरपाल, डीजल और बैटरी के साथ 7 पकड़ाये, 2 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। थाना लखनपुर पुलिस ने चोरी के दो मामलों में 7 आरोपितों को पकड़ा है, इनमें से दो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इनके पास से 7 नग तिरपाल, 50 लीटर डीजल और 1 बैटरी जप्त की गई है। दूसरे मामले में पुलिस ने झाड़ियों से एक तिरपाल बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पुहपुटरा के कुछ लोग चोरी का सामान छिपाकर रखे हैं। सूचना पर थाना टीम ने ग्राम पुहपुटरा में दबिश दी। पूछताछ में अरविन्द पैकरा 23 वर्ष, फेकू राम 40 वर्ष, जितेन्द्र कुमार 24 वर्ष, सरजू रजक 24 वर्ष, बुधन राजवाड़े 25 वर्ष और मनोज राजवाड़े 24 वर्ष सभी निवासी ग्राम पुहपुटरा ने चोरी का सामान रखना स्वीकार किया। पुलिस ने सामान जप्त करके धारा 35(3), 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देकर जांच शुरू की है।

साथ ही 2 लोगों पर धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया है। कार्रवाई में प्रशिक्षु उपनिरीक्षक हर्ष कुमार, एएसआई निर्मला कश्यप व परशु पैकरा, प्रधान आरक्षक प्रवीण चंद तिवारी, अजय पांडेय, पीताम्बर सिंह, महिला आरक्षक अमरावती राजवाड़े, आरक्षक दशरथ राजवाड़े, सुरेश गुप्ता, कुश सोनी, रामकुमार यादव सक्रिय रहे।

चलती ट्रक से तिरपाल चोरी करने वाला गिरफ्तार

लखनपुर थाना पुलिस ने ट्रक से तिरपाल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 7000 रुपये का एक नग वाटरप्रूफ तिरपाल बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक, फिरोज खान निवासी गढ़वा झारखण्ड ने 6 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह 4 जुलाई की रात को अमेरा खदान से कोयला लेकर जा रहा था। रास्ते में पुहपुटरा के बाडूल और अन्य युवकों ने मोटर सायकल से पीछा करके ट्रक से बंधा तिरपाल खोलकर चोरी कर लिया। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक के पीछे तरफ से आवाज आने पर जब वह ट्रक को रोका तो गाड़ी में बंधा वाटरप्रूफ तिरपाल नहीं था। युवक तिरपाल लेकर मोटर सायकल से भाग रहे थे। आरोपी खदान में आना-जाना तथा ट्रकों में तिरपाल बांधने का काम करते हैं, इसलिये वह इनको पहचानता था। पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। 15 जुलाई को ग्रामीणों ने बाडूल उर्फ सर्वजीत उर्फ विवेक राजवाड़े पिता अमर साय 22 वर्ष, निवासी पुहपुटरा को संदिग्ध हालत में पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में उसने साथियों के साथ मिलकर तिरपाल चोरी करना स्वीकार किया। निशानदेही पर नवापारा रोड के पास झाड़ी से तिरपाल बरामद करने में पुलिस सफल हुई है। आरोपी ने बताया कि वह अन्य साथियों के साथ मिलकर खदान आने-जाने वाले ट्रकों से डीजल और सामान चोरी करके बेच देता था। प्रकरण में अन्य आरोपी फरार हैं। इन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस लगी है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर